दैनिक
सांध्य प्रकाश
भोपाल की धड़कन
वर्ष 54/ अंक 311/ पृष्ठ 8 / मूल्य ₹ 2.10 संस्थापक- स्व. सुरेंद्र पटेल ■आर.एन.आई 22296/71 ■डाक पंजीयन मप्र/भोपाल/125/12-14
भोपाल, बुधवार 25 जून 2025 भोपाल से प्रकाशित dainiksandhyaprakash.in

सांध्यप्रकाश विशेष

आमिर खान ने की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात

नई दिल्ली। आमिर खान ने दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। बुधवार को ये मुलाकात दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में हुई, जहां आमिर ने अपनी हालिया रिलीज फिल्म सितारे जमीन पर की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी। इस दौरान फिल्म की पूरी कास्ट मौजूद थी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के आधिकारिक ङ्ग प्लेटफॉर्म से इसकी जानकारी देते हुए स्पेशल स्क्रीनिंग की तस्वीरें शेयर की गई हैं। पोस्ट में आमिर खान और द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर के साथ लिखा गया है, पॉपुलर फिल्ममेकर और एक्टर आमिर खान ने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की है।

अब सुनाई नहीं देगा, अमिताभ का साइबर ठगी से आगाह करने वाला संदेश

नई दिल्ली। अमिताभ बच्चन की आवाज में साइबर ठगी को लेकर आगाह करती डायलर टोन बंद कर दी गई। अभी तक यह डायलर टोन हर फोन कॉल पर सुनाई दे रही थी। यह मांग इंदौर के पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता ने उठाई थी, जिस पर एक ही दिन में अमल हो गया। दूरसंचार मंत्रालय स्तर पर इस डायलर टोन को बंद करने का निर्णय ले लिया गया। योगाभ्यास में शामिल होने इंदौर आए केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता ने इस बारे में ज्ञापन दिया था। एक दिन बाद दिल्ली में दूरसंचार मंत्रालय की बैठक में इस प्रस्ताव को रख दिया गया। मंगलवार से इस पर अमल भी हो गया। कुछ महीनों से हर मोबाइल फोन लगाने पर पहले साइबर ठगी से बचने का एक संदेश सुनाई देता, इसके बाद फोन की घंटी बजती।शनिवार को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर इंदौर आए केंद्रीय दूरसंचार मंत्री से एयरपोर्ट पर स्वागत के दौरान ही भाजपा नेता सुदर्शन गुप्ता ने इस बारे में बात की। उन्होंने शिकायत की थी कि साइबर ठगी के प्रति जागरूक करने का सरकारी प्रयास सराहनीय है। हालांकि, इसके लिए डायलर टोन बजाने की बजाए अन्य माध्यम चुने जाने चाहिए। पूर्व विधायक गुप्ता ने मंत्री से कहा कि दो बार ऐसा हुआ कि किसी दुर्घटना के दौरान मैंने एंबुलेंस को फोन लगाने की कोशिश की, तो डायलर टोन के कारण देरी लगी। लोग भी इससे परेशानी महसूस कर रहे हैं। इसके बाद मंत्री ने इस पर सहमति जताकर लिखित ज्ञापन पर तुरंत नोट भी लिख दिया था। इसके बाद मंगलवार से मोबाइल कॉल पर बीते दिनों से सुनाई दे रही डायलर टोन बंद भी हो गई। सोमवार को दिल्ली में आयोजित दूरसंचार मंत्रालय की बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया था कि डायलर टोन बंद की जाना चाहिए। इस पर सहमति दी गई और तुरंत इसे लागू करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए।

इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर बोले पीएम मोदी

लोगों को जेल में डाला संविधान को कुचला गया

आपातकाल

नई दिल्ली। आपातकाल को 50 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दौर को याद करते हुए एक्स पर पोस्ट लिखा, आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक, आपातकाल लागू होने के पचास साल पूरे हो गए हैं। भारत के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन, भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया।

मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया और कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया। ऐसा लग रहा था जैसे उस समय सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को बंधक बना लिया था।

कांग्रेस सरकार को लोकतंत्र बहाल करना पड़ा- प्रधानमंत्री ने कहा, हम आपातकाल के खिलाफ लड़ाई में डटे रहने वाले हर व्यक्ति को सलाम करते हैं! ये पूरे भारत से, हर क्षेत्र से, अलग-अलग विचारधाराओं से आए लोग थे जिन्होंने एक ही उद्देश्य से एक-दूसरे के साथ मिलकर काम किया। भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की रक्षा करना और उन आदर्शों को बनाए रखना जिनके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। यह उनका सामूहिक संघर्ष था जिसने यह सुनिश्चित किया कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार को लोकतंत्र बहाल करना पड़ा और नए चुनाव कराने पड़े, जिसमें वे बुरी तरह हार गए।

पीएम मोदी ने कहा, हम अपने संविधान के सिद्धांतों को मजबूत करने और विकसित भारत के अपने सपने को साकार करने के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराते हैं। हम प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुएं और गरीबों और वंचितों के सपनों को पूरा करें।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

आपातकाल कोई राष्ट्रीय आवश्यकता नहीं, बल्कि कांग्रेस और एक व्यक्ति की लोकतंत्र विरोधी मानसिकता का परिचायक था। शाह ने यह बात तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के संदर्भ में कही। इंदिरा गांधी सरकार ने 25 जून 1975 को आपातकाल लागू किया था। आपातकाल के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देते हुए शाह ने कहा कि यह दिन सभी को याद दिलाता है कि जब सत्ता तानाशाही बन जाती है, तो जनता उसे उखाड़ फेंकने की ताकत रखती है। गृह मंत्री ने कहा कि 'आपातकाल' कांग्रेस की सत्ता की भूख का 'अन्यायकाल' था।

राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोप कर देश के संविधान की हत्या कर दी थी। 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ चल रही है, उसकी नीयत आज भी वैसी ही तानाशाही वाली है। यह वह दिन है, जब जनता की ओर से पोषित लोकतंत्र की हत्या की गई। कांग्रेस पार्टी ने बनाए गए संविधान की हत्या की।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान

आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ आवाज उठाई, जिन्होंने लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए आंदोलन किया, जो संविधान की रक्षा के लिए जेल गए- मेरा मानना है कि यह आजादी के लिए तीसरा आंदोलन था... जब मैं जेल गया तो मेरी दादी बीमार हो गईं, बाद में उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे कई नेता थे, जिन्हें अपने परिवार के सदस्यों की मृत्यु पर अंतिम दर्शन में शामिल नहीं होने दिया गया।

आपातकाल लोकतंत्र का काला धब्बा: सीएम यादव

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आपातकाल की बरसी पर जमकर निशाना साधा है। सीएम ने 1975 में लगाए गए आपातकाल को लोकतंत्र पर धब्बा बताया। उन्होंने कहा- अपने निजी स्वार्थ के कारण से कांग्रेस की नेत्री(पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी) ने जो निर्णय लिया है इसे हम कभी नहीं भूलेंगे। साथ ही सीएम ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि, 'मैं अपने सभी लोकतंत्र सेनानियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देना चाहूंगा, जिनके कारण आज हमारा लोकतंत्र दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ है।

राकेश शर्मा के बाद शुभांशु शुक्ला दूसरे भारतीय हैं जो अंतरिक्ष में पहुंचेंगे

एक्सिओम 4 ने अंतरिक्ष के लिए भरी उड़ान

फ्लोरिडा। बार-बार टलने के बाद आखिरकार आज एक्सिओम 4 मिशन लॉन्च हो गया। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला समेत 4 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर ड्रैगन कैप्सूल अंतरिक्ष के लिए रवाना हो गया। इस मिशन की लॉन्चिंग सफल रही है। शुभांशु शुक्ला ने कहा कि अंतरिक्ष में मेरी उड़ान भारत की उड़ान है।

मैं हाथों में तिरंगा लेकर जा रहा हूं। नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से फॉल्कन 9 रॉकेट ने सफलतापूर्वकर उड़ान भरी है। कल शाम 4.30 बजे ये अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ेंगे। यह पूरा अभियान कुल 14 दिन का है। राकेश शर्मा के बाद शुभांशु शुक्ला दूसरे भारतीय हैं जिन्हें अंतरिक्ष में पहुंचने की उपलब्धि हासिल होने वाली है। शुभांशु शुक्ला ने कहा कि अंतरिक्ष में मेरी उड़ान भारत की उड़ान है। मैं हाथों में तिरंगा लेकर जा रहा हूं।

दोपहर 12 बजे लॉन्च हुआ मिशन

मिशन भारतीय समयानुसार दोपहर करीब 12 बजे फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। स्पेसएक्स के फाल्कन-9 रॉकेट से जुड़े ड्रैगन कैप्सूल में सभी एस्ट्रोनॉट ने उड़ान भरी। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट करीब 28.5 घंटे के बाद 26 जून को शाम 4.30 बजे आईएसएस से जुड़ेगा।

41 साल बाद कोई भारतीय फिर अंतरिक्ष में

अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और भारतीय एजेंसी इसरो के बीच हुए एग्रीमेंट के तहत भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को इस मिशन के लिए चुना गया है। शुभांशु इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। इससे 41 साल पहले राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा की थी।

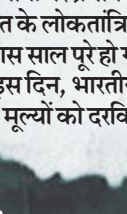

6 बार टाला गया एक्सिओम-4 मिशन- 29 मई को ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के तैयार नहीं होने के कारण लॉन्चिंग टाल दी गई। इसे 8 जून को शेड्यूल किया गया। फाल्कन-9 रॉकेट लॉन्च के लिए तैयार नहीं था। नई तारीख 10 जून दी गई। फिर से इसे मौसम खराब होने की वजह से टाला गया। चौथी बार 11 जून को मिशन शेड्यूल किया गया। इस बार आक्सीजन लीक हो गई। नई तारीख 19 जून दी गई।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से ज्योतिष मठ संस्थान भोपाल के संचालक पंडित विनोद गौतम ने समत्व भवन में भेंट की।

उत्तरी भारत में मौसम ने बदले मिजाज, दिल्ली-एनसीआर समेत 11 राज्यों में तूफान के साथ होगी झमाझम

नई दिल्ली। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, 25 जून से उत्तर-पश्चिम भारत के कई राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी। इन राज्यों में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। बिहार, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में आज से 28 जून तक मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में हुई नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की 267वीं बैठक

नर्मदा परियोजनाओं के संचालन में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित किया जाए - मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि नर्मदा नदी, राज्य की जीवनदायिनी है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत संचालित गतिविधियों से प्रदेश में सिंचाई के रकबे और ऊर्जा उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है और प्रदेशवासियों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। परियोजना के अंतर्गत निर्मित सिंचाई व्यवस्था में सौर ऊर्जा के उपयोग को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाए। जल उद्वहन में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने से बिजली पर होने वाले व्यय में कमी लाई जा सकेगी। किसानों को भी सिंचाई में सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाए। मां नर्मदा के जल का प्रदेश हित में अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की 267वीं बैठक मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में संपन्न हुई। अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, श्री मनीष रस्तोगी सहित प्राधिकरण के अन्य अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

बैठक में शहीद ईलाप सिंह माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना जिला हरदा, सेंधवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना जिला बड़वानी, निवाली उद्वहन सिंचाई परियोजना जिला बड़वानी, धार उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना, माँ रेवा उद्वहन सिंचाई परियोजना जिला देवास की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में निर्णय लिए गए। बैठक में निर्माणाधीन स्लीमनाबाद टनल के तकनीकी पहलुओं पर चर्चा हुई। इसके साथ ही डोबी सिंचाई परियोजना, भीकनगांव बिंजलवाडा माईक्रो सिंचाई परियोजना, आई.एस.पी.-पार्वती लिंक परियोजना, खालवा उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना जिला खण्डवा की समयवृद्धि प्रस्ताव पर बैठक में विचार-विमर्श हुआ।

मनीष भटनागर की सकुशल वापसी पर सीएम ने की बात

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इजरायल- ईरान युद्ध के चलते कतर में फंसी उज्जैन निवासी सुश्री मनीष भटनागर की सकुशल वापसी के बाद उनसे वीडियो कॉल पर चर्चा कर उनकी कुशलक्षेम पूछी। उल्लेखनीय है कि श्रीमती मनीष भटनागर कतर एयरवेज में सीनियर केबिन क्रू हैं। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने इस प्रकरण में उनकी सकुशल वापसी के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से सहयोग के लिए अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रदेश के संबंधित अधिकारियों को केंद्र सरकार के संपर्क में रहते हुए मनीषा की सकुशल स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे।

आपातकाल की विभीषिका पर संगोष्ठी कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम व इंदौर में 381 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे

इंदौर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज यानी बुधवार को इंदौर जिले के प्रवास पर रहेंगे। इंदौर पहुंचने के पश्चात वह स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इंदौर मीडिया सह प्रभारी नितिन द्विवेदी ने बताया कि सीएम आपातकाल की विभीषिका पर संगोष्ठी कार्यक्रम में शामिल होंगे।

नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने बताया कि, आपातकाल की विभीषिका के काले अध्याय के 50वें वर्ष में भारत के महान लोकतंत्र के संरक्षण व संविधान की रक्षा के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी इंदौर द्वारा ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर में आपातकाल की विभीषिका पर संगोष्ठी का आयोजन होगा। इसमें मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मुख्य वक्ता के रूप में राज्यसभा सांसद एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के साथ ही विशेष अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री अजय विश्नोई सम्मिलित होंगे।

381 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे- सूत्रों की मानें तो मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित करवाई सीनियर सिटीजन बिल्डिंग का लोकार्पण करेंगे। जिसमें 32 फ्लैट 16 करोड़ रुपए की लागत से बनवाए गए हैं। इसके साथ ही लगभग 381 करोड़ के अन्य विकास कार्यों की सौगात भी देंगे।

इजराइल से आज 224 भारतीय नागरिक लौटे

भारतीय दूतावास ने ईरान में ऑपरेशन सिंधु बंद किया, इजराइल-ईरान में सीजफायर के बाद फैसला

नई दिल्ली। ऑपरेशन सिंधु के तहत बुधवार सुबह 224 भारतीय नागरिक इजराइल से भारत लौटे। ईरान-इजराइल के तनाव के बीच दोनों देशों से अब तक 3394 भारतीयों को भारत लाया जा चुका है। इससे पहले 24 जून की रात 12.01 बजे 282 भारतीयों को लेकर एक फ्लाइट मशहद से दिल्ली पहुंची थी।

उधर, भारतीय दूतावास ने मंगलवार देर रात बताया था कि ईरान और इजराइल के बीच सैन्य संघर्ष के दौरान शुरू किए गए भारतीयों को निकालने के अभियान को बंद कर रहे हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो गया है। दूतावास ने इवैक्युएशन (लोगों को निकालने) के लिए नए नामों को रजिस्टर करने के लिए खोली गई डेस्क को बंद कर दिया।

हालांकि, X पर एक पोस्ट में दूतावास ने लिखा कि भारत ईरान के हालात पर बारीकी से नजर रख रहा है और अगर वहां मौजूद भारतीयों को किसी भी तरह का खतरा होता है तो हम अपनी रणनीति में बदलाव करेंगे।

भारत ने दोनों देशों के बीच बढ़ती दुश्मनी को देखते हुए, ईरान और इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए पिछले हफ्ते ऑपरेशन सिंधु शुरू किया था।

दूतावास ने कहा- जो जहां हैं वहीं रहें, हालात पर नजर रखें- भारतीय दूतावास ने ङ्ग पर लिखे पोस्ट में मशहद के लिए निकलने की प्लानिंग कर रहे भारतीयों को सलाह दी कि वे जहां हैं, वहीं रहें और खबरों पर नजर रखें। दूतावास ने पहले से होटल में रह रहे लोगों से कहा कि वे मशहद की सद्र होटल में चले जाएं, क्योंकि मिशन बाकी होटलों में कमरे खाली कर देगा।

कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तेज

बेगलुरु। कर्नाटक में सत्तापक्ष कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल भाजपा में फिर सियासी कलह जमीन पर नजर आने लगी है और स्थापित नेताओं के खिलाफ मुहिम उफान पर है। कांग्रेस विधायक और योजना आयोग के उपाध्यक्ष का एक ऑडियो क्लिप वायरल है, जिसमें वे भ्रष्टाचार व्याप्त होने का आरोप लगा रहे हैं। इससे राजनीतिक गलियारे में उबाल आ गया है और मुख्यमंत्री एन.सिद्धरामैया के खिलाफ चल रही मुहिम को हवा मिली है। उधर, भाजपा में जिलाध्यक्षों की नियुक्तियों ने प्रदेश नेतृत्व खासकर पूर्व सीएम येड़ियूरप्पा के पुत्र प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र के खिलाफ गुटबाजी को हवा दी है। दोनों दलों के गुट अपने-अपने पक्ष में माहौल बना रहे हैं, तो नेतृत्व के सामने डैमेज कंट्रोल की चुनौती है।

आंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर कांग्रेस उपवास कार्यक्रम

ग्वालियर। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित ÷संविधान सत्याग्रह उपवास÷ कार्यक्रम के तहत ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थापना की माँग को लेकर उपवास कार्यक्रम का आगाज हुआ। जिसमें मध्यप्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी शामिल हुए। इस उपवास में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के साथ मध्य प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कमलेश्वर पटेल सहित पार्टी के कई अन्य गणमान्य लोग साथ मौजूद रहे।

संन्यास - भौतिकता से सत्य की ओर

सन्यास का अर्थ एक न्यासी या ट्रस्टी की तरह जीवन व्यतीत करना होता है, सन्यास लेने या देने की चीज नहीं है, यह एक मानसिक भाव है। दीक्षा, आचरण के नियम, वेशभूषा, विधि आदि सम्प्रदाय, आश्रम विशेष या गुरु विशेष के होते है; पर संन्यास में इसकी कोई उपयोगिता नहीं है जब किसी भावनात्मक चोट से या स्वयं की विचार शक्ति से भौतिक जगत से मोह टूटता है, तो व्यक्ति स्वयं और स्वयं के जीवन का कारण तलाशने लगता है। सन्यास का प्रारंभ यहाँ से होता है, इसके लिए कोई नियम नहीं है - विधियाँ और नियम भौतिक साधनाओं के लिए होते है। सन्यास पूर्णतया भावनात्मक ज्ञानमार्ग है जो विचार शक्ति, तर्क शक्ति, मनन शक्ति के द्वारा भौतिकता का बेध कर अंतिम सत्य तक पहुँचाता है।

बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव

रानी दुर्गावती के नाम पर चिड़ियाघर व रेस्क्यू सेंटर बनाए जाने की घोषणा

सांध्य प्रकाश संवाददाता ● भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि रानी दुर्गावती अपने नाम के अनुरूप मां दुर्गा के समान वीर और पराक्रम की प्रतिमूर्ति थीं। आज उनका बलिदान दिवस है। रानी दुर्गावती का जन्म लगभग 500 वर्ष पहले हुआ था। अमेरिका सहित पश्चिम के देशों को सामान्य तौर पर संस्कृति में अग्रणी माना जाता है, लेकिन भारत का गौरवशाली अतीत रहा है। आदिवासी अंचल की रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई नारी सशक्तिकरण की सबसे बड़ी उदाहरण हैं। रानी दुर्गावती के पिता ने 500 साल पूर्व उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल में निपुण बनाया था। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार को जबलपुर के नर्ई नाला स्थित वीरांगना रानी दुर्गावती की समाधि पर श्रद्धासुमन अर्पित करने के बाद बारहा ग्राम में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जबलपुर का ठाकुरताल पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा। यहां भोपाल के वन विहार की तर्ज पर एक आधुनिक चिड़ियाघर (रेस्क्यू सेंटर एवं जू) बनाया जाएगा, यह सेंटर गौंडवाना साम्राज्य की वीरांगना रानी दुर्गावती को समर्पित होगा। यह वन्यप्राणी रेस्क्यू सेंटर रानी दुर्गावती के नाम से जाना जाएगा। राज्य सरकार रानी दुर्गावती सहित सभी महान हस्तियों का सम्मान करते हुए आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मैराथन जैसे आयोजनों के लिए नगर निगम जबलपुर को 5 लाख रुपए और कार्यक्रम में मनमोहक प्रस्तुति देने वाले प्रत्येक लोक कलाकार को 5-5 हजार रुपए देने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मोटे अनाज के प्रोत्साहन एवं उपार्जन के लिए रानी दुर्गावती के नाम पर योजना की प्रारंभ की है। रानी दुर्गावती ने अपने जीवनकाल में 52 लड़ाइयां लड़ीं और 51 में विजय श्री प्राप्त की। उनके गौंडवाना साम्राज्य में 23 हजार गांव शामिल थे। वीर रानी दुर्गावती ने 3 बार मुगल सेना को धूल चटाई थी। राज्य सरकार ने उनकी वीरता की कहानियों को

भोपाल के वन विहार की तर्ज पर जबलपुर में बनेगा आधुनिक चिड़ियाघर

स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया है। यह विरासत से विकास का एक क्रम है। वीरांगना दुर्गावती ने जल संरक्षण की दिशा में भी उल्लेखनीय प्रयास किए थे। उनके साथ इसी स्थान पर विश्वासघात हुआ था और उन्होंने वीरतापूर्वक अपना बलिदान कर दिया था। रानी दुर्गावती भी चंद्रशेखर आजाद की तरह आजाद रहीं दुश्मन उन्हें कभी हाथ नहीं लगा पाया। उन्होंने वीरांगनाओं को याद करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में रानी अवंतीबाई व रानी लक्ष्मीबाई की शौर्य व पराक्रम की अद्भुत गाथा है। वर्तमान समय में आदिवासी अंचल की बहन राष्ट्रपति पद को गौरवांवित कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि परिसीमन के बाद विधानसभा चुनाव में बहनों को भी 33 प्रतिशत आरक्षण देने की भावना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम के दौरान रानी दुर्गावती मैराथन दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले धावकों को चेक एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक रानी दुर्गावती को समर्पित करते हुए गोंडवाना की धरती पर करने का निर्णय लिया।

हिंदू पंचांग के अनुसार, 24 जून को शाम को 06 बजकर 8 मिनट पर आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत होगी। वहीं, इसका समापन अगले दिन यानी 2 5 जून को दोपहर 04 बजे होगा। पचांग गणना के आधार पर आषाढ़ अमावस्या 25 जून 2025 को मनाई जाएगी।

आषाढ़ अमावस्या का धार्मिक महत्व

आषाढ़ अमावस्या पितरों को समर्पित है। माना जाता है कि इस तिथि पर किए गए श्राद्ध कर्म से पितरों को मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। यह तिथि उन लोगों के लिए भी विशेष महत्व रखती है, जिन्हें अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि पता नहीं है। ऐसे में इस दिन दान-पुण्य, पितृ तर्पण और पिंडदान जरूर करें। इससे कुंडली में पितृ दोष शांत होता है।

पंडित लेखराज शर्मा ज्योतिषाचार्य 9893470412

कृष्णा गौर ने वार्ड 65 में किया 52 लाख रुपए के विकास कार्यों का किया भूमिपूजन

आई.टी.आई. स्टाफ कैंपस में 5 लाख रुपए की लागत से सांस्कृतिक मंच का होगा निर्माण

भोपाल। पिछड़ा वर्ग एव अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने कहा है कि बारिश का दौर शुरू हो गया है, इसलिए क्षेत्र में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने मंगलवार को भोपाल के वार्ड 65 में जनसंपर्क किया और 52 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों के भूमि-पूजन के दौरान अधिकारियों को यह निर्देश दिये।

राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि हमारा सतत प्रयास है कि जनहित से जुड़े हर कार्य को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने वार्ड 65 में आई.टी.आई. स्टाफ कैंपस में 5 लाख रुपए की लागत से निर्माण होने वाले सास्कृतिक मंच निर्माण कार्य का भूमि-पूजन किया। इस दौरान मौजूद आईटीआई के छात्रों से उन्होंने कहा कि आप देश का भविष्य है, इसलिए अपने अंदर स्किल डेवलप करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि क्षेत्र में उन्होंने एक पार्क का निर्माण भी कराया जाए। गौतम नगर की बस्ती में 14 लाख 88 हजार की लागत से आरसीसी नाली एवं सीसी रोड निर्माण कार्य का भूमि-पूजन किया। राज्य मंत्री श्रीमती गौर ने गायत्री नगर में जनसंपर्क के दौरान क्षेत्रवासियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को जाना। आदर्श नगर में जनसंपर्क के दौरान रहवासियों ने पेयजल, स्ट्रीट की लाइट स्थिति से अवगत कराया। चाणक्यपुरी में 5 लाख 57 हजार रुपए की लागत से होने वाले नाली निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया।

उन्होंने कहा यह कार्य क्षेत्र की स्वच्छता व जनसुविधा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। छत्रसाल नगर और भवानी धाम में जनसंपर्क कर रहवासियों की समस्याएं सुनी और त्वरित निराकरण किया। गीत बंगलो फेस- 5 में आरसीसी नाली और सीसी रोड निर्माण कार्य का भूमि-पूजन किया, जिसकी लागत 26 लाख रुपए है।

धार्मिक कार्यक्रमों के साथ मना दादाजी धाम मंदिर का 16वां स्थापना दिवस

सांध्य प्रकाश संवाददाता ● भोपाल

राजधानी के रायसेन रोड के पास पटेल नगर भोपाल स्थित दादाजी धाम मंदिर का 16 वां स्थापना हवन पूजन और भक्ति भाव से मनाया गया। इस मौके पर मंदिर में प्रात 9 बजे से पंडित द्वारा यजमानों से प्रथम पूज्य भगवान गणेशजी की पूजन प्रारंभ की गई। इसके बाद सभी भगवान, मुख्य शिखर पर विराजित चारो धाम एवं गर्भगृह परिक्रमा स्थल में स्थापित सभी संतो का अभिषेक, पूजन, हवन, आरती की गई। जिसमें ट्रस्ट के अध्यक्ष शिवरतन नामदेव , कोषाध्यक्ष अखिलेश श्रीवास्तव, ट्रस्टी जीवन नामदेव , मनोज मोहन, अनीता, अर्चना नामदेव एवं मंदिर व्यवस्था समिति के सदस्य आर.डी. धुर्वे, हर्ष, शुभ्रा,ओ.पी. राजपूत ने विधि विधान से सभी भगवान की पूजा की बाद में भक्तों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। भोपाल के विभिन्न क्षेत्रों से दादाजी के भक्त कार्यक्रम में उपस्थित हुए।

मंत्री सिंह ने मॉडल स्कूल की वार्षिक पत्रिका का किया विमोचन

भोपाल। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने मंगलवार को मंत्रालय में मॉडल स्कूल टीटी नगर, भोपाल की वार्षिक शालेय पत्रिका प्रस्तुति का विमोचन किया। मंत्री सिंह ने इस मौके पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि स्कूल की वार्षिक पत्रिका बच्चों की प्रतिभा को निखारने का एक अच्छा माध्यम है। उन्होंने पत्रिका के प्रकाशन पर शाला प्रबंधन के प्रयासों की प्रशंसा की। स्कूल की प्राचार्य रेखा शर्मा ने बताया कि शाला की वार्षिक पत्रिका में बच्चों की वर्षभर की खेल-कूद, सांस्कृतिक और प्रतिभाशाली बच्चों की उपलब्धियों का समावेश किया गया है। उन्होंने बताया कि पत्रिका में बच्चों के साइंस इनोवेशन, लेख और साहित्यिक रचनाओं को प्रमुख स्थान दिया गया है। प्राचार्य ने बताया कि स्कूल में कक्षा 6 से 12 तक करीब 2400 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। स्कूल प्रबंधन द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है। इस अवसर पर उप प्राचार्य आर.के. श्रीवास्तव, व्याख्याता आशा वैश एवं व्याख्याता शिशुपाल सिंह यादव उपस्थित रहे।

पोकर एक माइंड स्पोर्ट: एमपी के आईआईटीयन केशरवानी ने मनीमेकर टूर्नामेंट में अपना पहला ब्रेसलेट जीता

भोपाल। मध्य प्रदेश के चाकघाट से ताल्लुक रखने वाले 31 वर्षीय आदित्य केशरवानी ने PokerBaazi के प्रतिष्ठित ÷द मनीमेकर÷ टूर्नामेंट में जीत हासिल कर अपने करियर की एक बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। 1000 से अधिक प्रतिभागियों को पछाड़ते हुए, पूर्व आईआईटीयन ने अपना पहला प्रतिष्ठित ब्रेसलेट खिताब और 15 लाख रुपये की इनामी राशि अपने नाम की। आदित्य की यात्रा जितनी कौशल की है, उतनी ही व्यक्तिगत अनुशासन की भी है। मध्य प्रदेश के छोटे से शहर चाकघाट में पले-बढ़े आदित्य का पालन-पोषण एक पारंपरिक परिवार में हुआ, जहां उनकी शैक्षणिक प्रतिभा को शुरुआत से ही पहचाना गया। स्थानीय स्तर पर सीमित शैक्षिक संसाधनों को देखते हुए, उनके माता-पिता ने उन्हें प्रयागराज के एक बोर्डिंग स्कूल भेजने का महत्वपूर्ण फैसला लिया। वहां आदित्य ने न सिर्फ पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल की, बल्कि एक सर्वांगीण खिलाड़ी के रूप में भी उभरे, वे फुटबॉल, टेबल टेनिस, तैराकी और योग जैसी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे। बुद्धिमत्ता और खेल कौशल के इस संतुलन ने उनके पोकर करियर की नींव रखी, एक ऐसा माइंड स्पोर्ट जो मानसिक फुर्ती और भावनात्मक नियंत्रण दोनों की मांग करता है।

भारत भवन के अंतरंग सभागार में अथः नदी कथा वैचारिक समागम सम्पन्न

नदी और जल संरचनाओं का संरक्षण जनजागरण और सहयोग से ही संभव

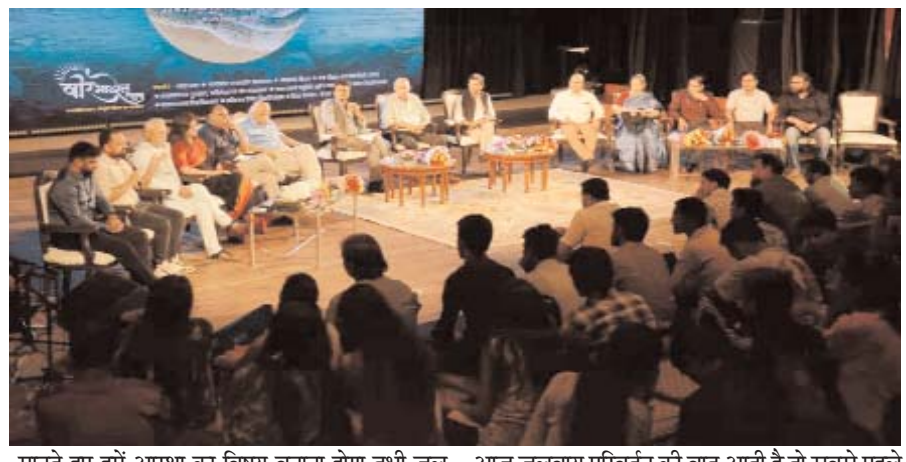

भोपाल। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत सदानीरा समागम के पाँचवें दिन भारत भवन के अंतरंग सभागार में जलीय जीव एवं जल संरचनाओं पर एकाग्र वैचारिक समागम का आयोजन हुआ। इस मौके पर सभी विद्वानों ने एक स्वर में कहा कि नदी तालाबों और जल संरचनाओं को संबोधित संरक्षित करने के लिए सरकार के साथ-साथ लोक समाज को भी आगे आना होगा। यह जनजागरण और सहयोग से ही संभव है। तभी हम अपना भविष्य सुरक्षित कर पाएंगे। वरिष्ठ लेखक व पत्रकार अजय बोकिल ने कहा कि पानी को बचाने, साफ रखने और उसके महत्व को कायम रखने के लिए भोपाल सबसे बड़ा उदाहरण है। एक समय ऐसा भी आया जब बड़े तालाब का पानी मूर्ति और ताजिया विसर्जन के चलते दूषित होता चला गया था। मतलब पीने योग्य नहीं था तब भोपालवासियों ने यह तय किया कि तालाब में मूर्ति विसर्जन नहीं किया जाएगा इसके लिए अलग से कुंड बनाए जाएंगे ऐसा करने पर पहले की तुलना में तालाब का पानी साफ भी हुआ और शुद्ध भी। यह एक ऐसा उदाहरण है जिसे अन्य स्थानों पर भी लागू किया जाना चाहिए। वरिष्ठ साहित्यकार श्री संतोष चौबे ने कहा कि जल संरचनाओं और नदियों को संरक्षित करने के लिए पानी के पक्ष में जन अभियन चलाया जाना चाहिए। आज इस विषय पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है और जल संरचनाओं को बचाने के लिए प्रदेश और देश के दुनिया के मॉडलों को अपनाना चाहिये।

इस मौके पर वरिष्ठ पुरातत्वविद श्री शिवाकांत वाजपेई ने कहा कि जल जीवन और जन्म त्रिवेणी हैं। इसे हमें समझना होगा। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के अन्वेषणकर्ता श्री आरोह श्रीवास्तव ने जल और समय पर चर्चा की। उन्होंने फ्रेश वाटर को लेकर सुझाव दिया कि हमारे जीवन में फ्रेश वाटर का इस्तेमाल बहुत कम होता है, लेकिन दैनिक दिनचर्या में इस फ्रेशवाटर को हम वेस्टेज के रूप में इस्तेमाल कर देते हैं यह चिंता का विषय है। मथुरा के युवा शोधकर्ता श्री योगी अनुराग ने नदियों के महत्व को बताते हुए उन्हें संरक्षित करने की बात कही। श्री संजय सिंह ने जल संरचनाओं को संरक्षित करने के लिए विज्ञान का विषय न मानते हुए हमें आस्था का विषय बनाना होगा तभी जल स्त्रोतों नदियों और पानी को बचाया जा सकता है।वरिष्ठ चिकित्सक श्री राजेश शर्मा ने नदियों को आरोग्य कैसे रखें इस पर बात करते हुए कहा कि सबसे पहले हमें नदियों के रोग को, उसमें पनप रहे कीटाणुओं को समझना होगा। यह कीटाणु, यह रोग, हम खुद हैं, उद्योग हैं, जो नदियों को पवित्र बनाने से रोक रहे हैं। हमें याद है कोविड का समय जब नदी की पवित्रता और उसमें जल जीव स्वतंत्र रूप से रह रहे थे। हम खुद ये कहने लगे थे कि प्रत्येक साल लॉकडाउन जैसी स्थिति बन जानी चाहिए ताकि हमारी नदी, जल संरचनाएं पवित्र हो सके।

युवा पत्रकार सुश्री मीणा जांगिड़ ने कहा कि जल का विषय सरकार का नहीं समाज का विषय होना चाहिए। हमारी प्राचीन परंपराएं पानी के महत्व को बताती आई हैं इसे भविष्य में भी कायम रखने की जरूरत है। डॉ. रमेश यादव ने भोपाल के बड़े तालाब का जिक्र करते हुए कहा कि राजा भोज ने जिस झील को बनाया आज उसे बचाने की बात आ रही है। प्राचीन काल में लोग नदियों की पवित्रता को ध्यान में रखते थे नदियों में कभी भी दूषित पानी नहीं जाने देते थे। आज जल स्त्रोतों को संरक्षित करने की जरूरत है तभी भविष्य सुरक्षित हो सकता है। डॉ. इंदिरा खुराना ने कहा कि आज जलवायु परिवर्तन की बात आती है तो सबसे पहले कार्बन उत्सर्जन की बात की जाती है। लेकिन जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रभाव यदि किसी पर पड़ता है तो वह पानी पर पड़ता है। जैसे बाढ़ का आना, ग्लेशियर का पिघलना, समुद्र में तूफान, अकाल पड़ना आदि यह वैश्विक चुनौतियां भी बनाकर हमारे सामने हैं। पारंपरिक ज्ञान से ही है इन आपदाओं से बचा जा सकता है। आज विकेंद्रित जल प्रबंधन की दिशा में कार्य करने की जरूरत है। वरिष्ठ अधिकारी श्री नागार्जुन गौड़ा ने कहा जल संचय-जल भागीदारी अभियान ने देश भर में एक नई पहचान बनाई है। जिसके चलते खंडवा देश का नंबर वन शहर बनकर सामने आया है। हमने 1 लाख 30 हजार से अधिक स्ट्रक्चर्स तैयार किये जिसमें वाटर रिचार्ज का काम हुआ। इस अभियान का मुख्य बिंदु रूफ वाटर हार्वेस्टिंग था जिसके चलते लाखों लीटर पानी को संचित किया गया। समागम का समन्वय माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी, विस्तार न्यूज़ के चैनल हेड श्री ब्रजेश राजपूत ने किया। इसके पहले भूमिका वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव श्रीराम तिवारी ने रखी और जल गंगा संवर्धन अभियान की जानकारी दी और समागम की आवश्यकता को बताया।

प्रदेश के 413 नगरीय निकायों में हुई जल सहेजने की गतिविधियां

भोपाल। प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में नगरीय क्षेत्रों में जल गंगा संवर्धन अभियान में सामूहिक जनभागीदारी से जल सहेजने के लिये 413 नगरीय निकायों में 30 मार्च से विभिन्न गतिविधियां निरंतर संचालित हो रही हैं। इस कार्य में जनप्रतिनिधियों ने भी बढ़-चढ़ कर हिस्सेदारी की। नगरीय निकायों में जल स्त्रोतों का संरक्षण व पुनर्जीवन, जनसामान्य में जल संचय और संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता का विकास, सामूहिक सहभागिता से स्थाई जल संरचनाएं विकसित करने के साथ ही नदियों, तालाबों, कुओं, बावड़ियों और पारंपरिक जल स्त्रोतों के जीर्णोद्धार का कार्य प्रमुख रूप से किया गया।

नर्मदा नदी से लगे शहरी क्षेत्र में घाटों की मरम्मत और सफाई कार्य को प्राथमिकता दी गई। नगरीय निकायों में 3300 से अधिक जल स्त्रोतों को पुनर्जीवन दिया गया। नगरीय क्षेत्र के 2200 नालों की सफाई और पुर्नसंचालन की क्षमता विकसित की गई। प्रदेश में 4 हजार वर्षा जल संचयन संरचनाएं तैयार की गई। प्रदेश के प्रमुख नगरों में 32 अमृत जल संरचनाएं एवं 38 हरित क्षेत्र कार्य पूर्ण किये गये। नगरीय निकायों के कर्मियों ने शहरी क्षेत्रों में जल गुणवत्ता का परीक्षण फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल मानकों पर किया गया। मार्च 2025 से शुरू हुए अभियान में गर्मी के मौसम को देखते हुए नगरीय क्षेत्रों में 2700 सार्वजनिक प्याऊ और जल केन्द्रों की व्यवस्था की गई। इस पूरे अभियान में जनसहभागिता अभियान की आत्मा रही। अभियान में 70 हजार से अधिक नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 341 कलश यात्राएं नगर के प्रमुख मार्गों से निकाली गईं। इनमें महिलाओं की भागीदारी प्रमुख रही। अभियान से जुड़े 1000 जल नायक और जल मित्रों का माय भारत पोर्टल पर पंजीयन किया गया।

सांध्यप्रकाश विशेष

त्वरित टिप्पणी

जी. के. छिब्बर

बेन डकेट का शतक ऋषभ पंत के 2 शतकों पर भारी इंग्लैंड के अनुभव की जीत

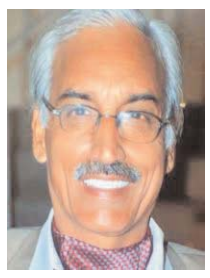

भारत और इंग्लैड का प्रथम क्रिकेट टेस्ट पूरे पांच दिन ओर दोनो टीमों ने पहली पारी में 400 से अधिक रन बनाए दुसरी पारी में 300 से अधिक रन बनाए इसके बावजूद परिणाम निकला यह टेस्ट क्रिकेट के लिए शुभ संकेत है। इंग्लैड की विजय में अनुभव था जबकि भारतीय टीम में युवा जोश था

भारतीय टीम के पांच शतक लग जाने के बाद टेस्ट में पराजित होना गेंदबाजी पर सवाल उठना स्वाभाविक है प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज जोश में गेंदबाजी कर रन लुटाते रहे इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने दूसरी पारी में बुमराह ओर जडेजा की गेंदबाजी को रोकते रहे उनकी इसी रणनीति ने भारत को पराजित किया। कप्तान शुभमन गिल ने जडेजा से आखिरी दिन देर से गेंदबाजी कराई और शार्दुल ठाकुर को भी सीमित ओवर दिए बुमराह से अधिक गेंदबाजी कर था थका दिया जो अंतिम सत्र में बाहर बैठे थे। फील्डिंग का स्तर घटिया था दोनों परियों में लगभग 8 कैच छोड़े

क्षेत्ररक्षण कमजोर रहा जो भी हार का प्रमुख कारण रहा। इंग्लैंड की विजय के शिल्पकार बेन डकेट रहे जिन्होंने 170 गेंदों में 149 रनों की धुंआधार पारी खेली और ऋषभ पंत के दो शतकों की भुला दिया यह कहा जा सकता है कि भारत की कमजोर गेंदबाजी पराजय का मुख्य कारण है कप्तान शुभमन गिल यूवा है उन्हें अनुभव की आवश्यकता है

राष्ट्रीय टेक-हैकाथॉन में तलाशे जायेंगे सिंहस्थ-2028 के लिए स्मार्ट टेक-सॉल्यूशंस

भोपाल। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने राष्ट्रीय टेक हैकाथॉन के माध्यम से सिंहस्थ 2028 के लिए स्मार्ट-टेक सॉल्यूशंस की खोज कर रहा है। हैकाथॉन का उद्देश्य पूरे देश के प्रतिभाशाली नवाचारकर्ताओं को एक मंच पर लाकर ऐसे स्मार्ट और व्यावहारिक तकनीकी सॉल्यूशंस विकसित करना है, जिससे दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजनों में से एक सिंहस्थ के प्रबंधन, सुरक्षा को पुख्ता और श्रद्धालुओं के अनुभव को सुखद बना सकें। हैकेथॉन में भाग लेने के लिये पंजीयन प्रक्रिया 26 जून 2025 से प्रारंभ होगी।हैकाथॉन में भाग लेने के लिए पंजीकृत स्टार्ट-अप्स, एमएसएमई, निजी कंपनियाँ, मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान और शोध संगठन पात्र होंगे। किसी पंजीकृत संस्था से संबद्ध विद्यार्थी और स्वतंत्र डेवलपर्स भी हैकाथॉन में व्यक्तिगत रूप से भाग ले सकेंगे। चयनित टीमों को डीपीआईआईटी स्टार्ट अप सर्टिफिकेट, एमएसएमई/उद्योग पंजीयन, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दस्तावेज़ या संस्थान के पहचान पत्र जैसे प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। हैकाथॉन के लिये चार थीम तय की गई है। चार थीमों में स्मार्ट मोबिलिटी एवं एक्सेस मैनेजमेंट, सुरक्षा, निगरानी और आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन, डिजिटल अनुभव और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति जैसे विषयों पर फोकस किया जाएगा। चयनित प्रतिभागियों को आइडिया-प्रेजेंटेशन, प्रोटोटाइप निर्माण और फाइनल प्रतियोगिता के कई चरणों से गुजरना होगा। यहां वे अपने समाधान सरकारी अधिकारियों, उद्योग विशेषज्ञों और तकनीकी नेतृत्व के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। हैकेथॉन के माध्यम से उज्जैन में यातायात की सुगमता, पार्किंग प्रबंधन, रूट ऑप्टिमाइजेशन और वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों के लिए सुलभ आवाजाही सुनिश्चित करने वाले सॉल्यूशंस, रीयल टाइम क्राउड मैनेजमेंट, आपातकालीन प्रतिक्रिया, एआई आधारित निगरानी और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों के लिए पूर्वानुमान लगाने वाले उपकरणों, स्वच्छ जल आपूर्ति और त्वरित चिकित्सा सहायता के लिए स्मार्ट टेक-सॉल्यूशंस प्रस्तुत किये जाएंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को वैश्विक मंच पर दी नई पहचानः मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव

केन्द्रीय गृह मंत्री शाह की अध्यक्षता में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री ने की सहभागिता

सांध्य प्रकाश संवाददाता ● भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश ने न केवल आंतरिक विकास की दिशा में ऐतिहासिक प्रगति की है, बल्कि वैश्विक मंच पर भी भारत की आवाज़ को निर्णायक और सम्मानजनक मान्यता मिली है। ऑपरेशन सिंदूर इस बात का प्रतीक है कि भारत अब अपने नागरिकों की सुरक्षा, सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने यह विश्वास दिलाया है कि हर भारतीय, चाहे वो कहीं भी हो, भारत सरकार उसकी ढाल बनकर खड़ी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार को वाराणसी में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में सहभागिता कर संबोधित कर रहे थे। बैठक में उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित उक्त राज्यों के मुख्य सचिव, केंद्र सरकार एवं संबंधित राज्य के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज भारत विकसित भारत 2047 के जिस मार्ग पर चल रहा है, उसमें राज्यों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। नीति आयोग, मुख्यमंत्री परिषद् और क्षेत्रीय परिषद जैसे संस्थागत तंत्र ने इन्हें केवल संवाद का साधन नहीं, बल्कि %समाधान का माध्यम बनाया है। हमें सिखाया गया है कि विचारधाराएँ अलग हो सकती हैं, लेकिन देश का भविष्य साझा है; दृष्टिकोण भिन्न हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य एक सशक्त, समावेशी और आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह क्षेत्रीय परिषद केवल प्रशासनिक विचार-विमर्श का मंच नहीं, बल्कि सहकारी संघवाद की जीवंत अभिव्यक्ति है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हमेशा इस बात पर बल दिया है कि भारत की शक्ति उसकी विविधता में है लेकिन उसकी गति, उसका विकास टीम इंडिया की भावना में निहित है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बाबा विश्वनाथ की धरती काशी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन हो रहा है। हमारा सौभाग्य है कि हम भगवान श्रीराम, आराध्य श्रीकृष्ण की जन्मस्थली और भगवान शिव के प्रिय निवास स्थान उत्तर प्रदेश की पुण्यभूमि पर एकत्रित हुए हैं। भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को केवल संवैधानिक प्रावधान नहीं बल्कि संवेदनशील नेतृत्व और संकल्प की शक्ति ही जीवंत बनाती है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में देखा गया है कि चाहे आपदा प्रबंधन हो, आंतरिक सुरक्षा या अधोसंरचना विकास, जब राज्य एकजुट होकर कार्य करते हैं, तो भारत की गति दोगुनी हो जाती है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के प्रयासों से राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ नियमित संवाद, केंद्र-राज्य समन्वय समितियाँ और निवेश सम्मेलन इन सभी माध्यमों से संघीय व्यवस्था को नया बल मिला है। प्रधानमंत्री ने इस धारणा को बदल दिया है कि राज्य और केंद्र प्रतिस्पर्धी हैं। अब हम राज्य और केंद्र साझेदार हैं, इस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 में लागू की गई थी। योजना अंतर्गत स्श्नष्ट के हितग्राहियों पर होने वाले व्यय का वहन भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा 60ञ्च40 के अनुपात में किया जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा प्रतिवर्ष प्रति परिवार व्यय की अधिकतम सीमा राशि 1052 रूपये सीलिंग निर्धारित की गई है, जो कि वर्ष 2018 से आज तक यथावत है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्धारित सीलिंग को बढ़ाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य विभागों में अलग-अलग पोर्टल होने के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पैरामीटर को ट्रैकिंग करने में कठिनाई आ रही है इसका समाधान करने के लिए एक इंटीग्रेटेड पोर्टल विकसित किए जाने की आवश्यकता है। बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश की उपलब्धियों और विकास संबंधी जानकारियां प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि प्रदेश के अधिकारी एवं कर्मचारी की 9 वर्षों से पदोन्नतियां रुकी हुई थीं। ऐसी स्थिति में राज्य शासन की कार्य दक्षता एवं कर्मचारियों की पदोन्नति कर्मचारियों की नवीन नियुक्तियां एवं लोक सेवकों के मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा था। इसका निराकरण करते हुए मध्यप्रदेश में लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 स्वीकृत किए गए हैं। जिससे प्रदेश के 5 लाख कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। पदोन्नति से जो 2 लाख पद खाली होंगे उनसे सीधी भर्ती के पदों पर नवीन नियुक्तियां की जा सकेगी। इस ऐतिहासिक निर्णय से शासकीय कर्मचारी के मनोबल में वृद्धि होगी एवं राज्य शासन की कार्य दक्षता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शहरी क्षेत्र को नीति आयोग के ग्रोथ हब मॉडल के अनुरूप औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र के हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। मध्यप्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास अधिनियम 2025 पारित कर इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर को उनके आसपास के जिलों को साथ में लेकर मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित करने की रणनीति तैयार की गई है। वर्तमान में प्रदेश में 17 शासकीय मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं शीघ्र ही सिंगरौली और श्योपुर में नए शासकीय मेडिकल कॉलेज प्रारंभ होंगे। अगले दो वर्षों में 6 नए शासकीय मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएंगे और उज्जैन में मेडिसिटी का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। राज्य शासन ने पीपीपी मॉडल पर 12 मेडिकल कॉलेज की स्थापना का निर्णय लिया है इसमें चार मेडिकल कॉलेज को सफलतापूर्वक अवार्ड कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश शासन शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर को कम करने में निरंतर प्रयासरत है। स्वास्थ्य, शिक्षा, जनजाति और पेयजल विभागों के विशेष कार्य दल गठन कर जमीनी स्तर पर कार्य किया जा रहा है। जन्म से 5 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं के पोषण स्तर में सुधार आया है मिशन वात्सल्य एवं पोषण 2.0 के तहत 12 लाख 51 हजार बच्चों को कुपोषण से बाहर निकाला गया है। ग्राम पंचायत स्तर पर नागरिकों को सामान्य सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी के लिए सरकार ने ई पंचायत परियोजना शुरू की है। मुख्य सामान्य सेवाओं में जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र, विवाह प्रमाण-पत्र, निर्माण परमिट निवास का प्रमाण और मनरेगा से संबंधित सेवाएं शामिल है। संपदा 2.0 पोर्टल के माध्यम से संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को डिजिटल बनाया गया है जिससे प्रॉपर्टी की खरीदी बिक्री आसान और पारदर्शी हो गई है।मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश को दूध कैपिटल बनाने की दिशा में हम प्रयासरत हैं। राज्य में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और मध्यप्रदेश दुग्ध संघ के बीच समझौता हुआ है। यह एग्रीमेंट डेयरी नेटवर्क को सशक्त करेगा और सांची ब्रांड को मजबूती मिलेगी। अगले 5 साल में प्रदेश के कम से कम 50त्न गांव में प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियां की स्थापना का लक्ष्य है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के निर्देश पर प्रदेश में दूध संकलन 10 लाख लीटर से बढ़कर 50 लाख लीटर करने का लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बच्चों से जुड़े संवेदनशील अपराधों के शीघ्र न्याय के लिए फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की गई है। वर्ष 2025 में क्हस्ट्स्ह में दर्ज प्रकरणों की जांच पूरी करने की दर 70. 87त्न और स्ब्ढ्क्र मामले के निपटान की दर 61.38त्न रही है। पिछले कुछ वर्षों में निराकृत किए गए मामले कई बार दर्ज मामलों से ज्यादा रहे, फिर भी लंबित मामलों की संख्या कम नहीं हुई इसलिए फास्ट्रैक कोर्ट के कामकाज को और बेहतर बनाने, जरूरी संसाधन बढाने और नियमित निगरानी करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्षा के जल को संग्रहित करने और पुराने जल स्त्रोतों के जीर्णोद्धार के लिये प्रदेश में 30 मार्च से 30 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। जनभागीदारी पर केन्द्रित इस अभियान में व्यापक सफलता मिली है। प्रदेश के सभी जिलों में जिला प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों और आम नागरिकों ने भी अभियान में अपनी सहभागिता निभाई है। परिणामस्वरूप प्रदेश में व्यापक जल संरचनाओं का निर्माण, नदियों के उदगम स्थल का सौन्दर्यीकरण सहित जल संवर्धन के अनेक कार्य हुए हैं। उन्होंने बताया कि आगामी माहो में जल गंगा संवर्धन अभियान के बाद अब पौध-रोपण का व्यापक अभियान चलाया जायेगा।

सारंग-गौर ने भोपाल में बढ़ाया हौसला

आपातकाल में वाजपेयी 18 माह जेल में रहे, राजमाता को तिहाड़ में रखा

आज, 25 जून 2025 को उस दिन को पचास वर्ष हो चुके हैं। इस घटनाक्रम में मध्यप्रदेश की भूमिका और पीड़ा दोनों ही अभूतपूर्व रही

25 जून 1975...यह तारीख भारतीय लोकतंत्र के माथे पर अंकित ऐसा धब्बा है, जिसे समय भी मिटा नहीं सका। यह वह रात थी, जब सरकार ने जनता के अधिकार छीन लिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की और पूरा देश मानो अंधकार में घिर गया। आज, 25 जून 2025 को उस दिन को पचास वर्ष हो चुके हैं। इस घटनाक्रम में मध्यप्रदेश की भूमिका और पीड़ा दोनों ही अभूतपूर्व रहीं हैं।

मध्यप्रदेश ने इस अघोषित तानाशाही के विरोध में ऐसा प्रतिरोध पेश किया, जिसे आने वाली पीढ़ियां आदर्श के रूप में याद करती रहेंगी। मीसा कानून के तहत हजारों लोगों को केवल इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि वे असहमति जताते थे। सवाल पूछते थे या सड़कों पर उतर आए थे। प्रदेश में उस वक्त करीब करीब हर जिले में गिरफ्तारियों की झड़ी लगी थी, अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई थी। रेडियो-टीवी जैसे माध्यम सरकार की आवाज बनकर रह गए थे। आपातकाल के दौरान जनसंख्या नियंत्रण अभियान के नाम पर जबरन नसबंदी जैसी कार्रवाइयों से गांवों में डर और असंतोष का फैला गया। गांव-गांव में सरकारी अमला लोगों को जबरन नसबंदी शिविरों में ले जाता, विरोध करने वालों को पीटा जाता और समाज को मानसिक दहशत में जीने के लिए मजबूर कर दिया गया। इसी अंधकार के दौर में कुछ ऐसे भी चेहरे उभरे, जिन्होंने लोकतंत्र की मशाल को बुझने नहीं दिया। भोपाल में स्कूल-कॉलेज के छात्रों ने जेल भरो आंदोलन में हिस्सा लिया। इसी आंदोलन में वरिष्ठ नेता कैलाश सारंग ने संरक्षक की भूमिका निभाई। बाबूलाल गौर जेल में अपने चुटकुलों और सकारात्मकता से बंदियों का हौसला बढ़ाते रहे। युवा शिवराज सिंह चौहान भी उस समय जेल गए थे।

इस आंदोलन का आलोक प्रदेश तक सीमित नहीं रहा। तिहाड़ जेल में बंद रहीं ग्वालियर की राजमाता विजयाराजे सिंधिया की गाथा भी उतनी ही प्रेरणादायक है। 3 सितंबर 1975 को उन्हें आर्थिक अपराध की धारा में गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेजा गया। उनकी आत्मकथा प्रिंसेज में वे लिखती हैं, मैं कैदी नंबर 2265 थी... जब मैं तिहाड़ पहुंची तो जयपुर की महारानी गायत्री देवी ने स्वागत किया। हमने एक-दूसरे का अभिवादन किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आपातकाल के दौरान 18 महीने जेल में रहे। वहीं से उन्होंने अपनी कविताओं के जरिए सरकार की नीतियों पर तीखी चोट की। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, तब वाजपेयी विदेश मंत्री बनाए गए। फिर बाद के दिनों में सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हुआ और देश पटरी पर आया। मीसा यानी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, 1971 में बनाया गया था। आपातकाल के दौरान इसका दमनकारी रूप सामने आया। यह कानून सरकारी एजेंसियों को मनमाने तरीके से किसी को भी बंदी बनाने का अधिकार देता था। लाखों लोग बिना आरोप या मुकदमे के जेलों में रहे। 25 जून 1975 की रात को जयप्रकाश नारायण की गिरफ्तारी से जो सिलसिला शुरू हुआ, वह मधु लिमये, मोरारजी देसाई, नानाजी देशमुख, प्रमिला दंडवते, लालकृष्ण आडवाणी, भैरों सिंह शेखावत, रघुवीर सिंह कुशवाहा और सैकड़ों नेताओं की गिरफ्तारी तक जा पहुंचा। कहा जाता है कि मीसा के तहत लगभग एक लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से कई को बाद में रिहा कर दिया गया तो कई को मीसाबंदी में तब्दील कर दिया गया।

प्रदेश में केश शिल्पी समाज के विकास के लिये हर संभव प्रयास होंगेः भोंडवे

नगर निगम क्षेत्र में लगाये जायेंगे 5 लाख पौधे

भोपाल। आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री संकेत एस. भोंडवे ने आज रविंद्र भवन स्थित अंजनी हॉल में आयोजित केश शिल्पी समाज की विशेष बैठक में सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केश शिल्पी समाज के विकास के लिये हर संभव प्रयास किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान युग नवाचार, सूचना प्रौद्योगिकी, मोबाइल ऐप और एग्रीगेटर तकनीकों का युग है। केश शिल्पी समाज को इन आधुनिक उपकरणों के साथ तालमेल बैठाते हुए आगे आना होगा।

आयुक्त नगरीय प्रशासन ने कहा कि समाज में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, लेकिन जो जितना सीखेगा, उतना ही लाभ उठायेगा और अपनी दक्षता को बढ़ा सकेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन योजना, छात्रवृत्ति, लाड़ली बहना योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ उठाने की अपील केश शिल्पी समाज से की। आयुक्त ने कहा कि केश शिल्पी समाज का पात्र व्यक्ति यदि सरकारी योजनाओं से वंचित है, तो उस वर्ग को लाभ दिलाने की जिम्मेदारी केश शिल्पी मण्डल की है।

आयुक्त नगरीय प्रशासन ने कहा कि अमृत हरित महा-अभियान के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के लिये व्यापक स्तर पर पौध-रोपण किया जायेगा। पौधों की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्व-सहायता समूह की महिलाओं को सौंपी जायेगी। उन्होंने केश शिल्पी समाज के प्रतिनिधियों से प्रत्येक नगर निगम क्षेत्र में कम से कम 5 लाख पौध-रोपण करने में सक्रिय सहयोग देने की अपील की। उन्होंने बताया कि भवन निर्माण में पौध-रोपण करने को अनिवार्य किया गया है। बिल्डिंग परमीशन में यह शर्त लागू कर दी गयी है। कार्यक्रम में केश शिल्पी मण्डल के अध्यक्ष श्री नंदकिशोर वर्मा ने मण्डल की गतिविधियों की जानकारी दी।

मध्यप्रदेश 25 हजार ईवीएम महाराष्ट्र को देगा दोनों निर्वाचन आयोग के बीच हुआ एमओयू

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग 25 हजार इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को स्थानीय निर्वाचन के लिये किराये पर देगा। इस संबंध में मंगलवार को मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग और महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग के बीच एमओयू हुआ।

आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग श्री मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि सहयोगी संघवाद की अवधारणा के अनुरूप आयोग महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग की जरूरत अनुसार उन्हें ईव्हीएम उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके पूर्व छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग को भी ईव्हीएम उपलब्ध करवाई गई थी। महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त श्री दिनेश वाघमारे ने मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त का ईव्हीएम उपलब्ध कराने के लिये आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में एक साथ स्थानीय निर्वाचन करवाना है, इसके लिये अत्यधिक संख्या में ईव्हीएम की जरूरत थी। श्री वाघमारे ने कहा कि मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ईव्हीएम उपलब्ध कराने पर वे आसानी से निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी करा सकेंगे। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री अभिषेक सिंह ने मध्यप्रदेश के स्थानीय निर्वाचन में उपयोग की जा रही ईव्हीएम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक कंट्रोल यूनिट और तीन बैलेट यूनिट का कुल किराया 1000 रूपये होगा। महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को कुल 25 हजार कंट्रोल यूनिट और 75 हजार बैलेट यूनिट उपलब्ध करवाई जायेंगी इनसे 2 करोड़ 50 लाख रूपये प्रतिभूति राशि के रूप में लिये जायेंगे। श्री सिंह ने बताया कि?निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होते ही महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग तुरंत ईव्हीएम वापस करेंगे। एमओयू के क्रियान्वयन के लिये 4 वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम बनाई जायेगी, जिसमें 2 अधिकारी मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के एवं 2 अधिकारी महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग के होंगे। इस दौरान सचिव महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग श्री सुरेश काकाणी एवं राज्य निर्वाचन आयोग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

ग्राम पंचायतों को मिलेगा सशक्तीकरण, पारदर्शिता व स्थायित्व : मंत्री पटेल

भोपाल। पंचायत एवं ग्रामीण विकास के तत्वावधान में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की उच्चस्तरीय बैठक में ग्राम रोजगार सहायक मार्गदर्शिका-2025 को औपचारिक रूप से लागू करने की घोषणा की गई। इस ऐतिहासिक निर्णय में पंचायत, ग्रामीण विकास एवं श्रम विभाग के मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल की सशक्त नेतृत्व भूमिका रही। श्री पटेल ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस नई मार्गदर्शिका को ÷स्थानीय रोजगार व्यवस्था में स्थायित्व, जवाबदेही और दक्षता का आधुनिक रूपांतरण÷ बताया। श्री पटेल ने कहा कि यह दस्तावेज ग्राम रोजगार सहायकों के चयन, मूल्यांकन और अनुशासन को लेकर आने वाले वर्षों की ग्रामीण विकास संरचना की रीढ़ सिद्ध होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि मार्गदर्शिका 2025 का तत्काल प्रभाव से क्रियान्वयन किया जाएगा, जिसके तहत सभी नियुक्तियां, मूल्यांकन, नवीनीकरण एवं अनुशासन की प्रक्रिया संचालित की जाएगी। चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए अब सभी नियुक्तियां लिखित परीक्षा के माध्यम से की जाएंगी, जिससे योग्य और स्थानीय युवा ग्रामीण विकास से सीधे जुड़ सकेंगे। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि ग्राम रोजगार सहायक केवल संविदा कर्मी नहीं, बल्कि ग्रामीण नव निर्माण के मूल स्तंभ हैं। यह मार्गदर्शिका उन्हें न केवल दिशा देगी, बल्कि गरिमा, संरक्षण और प्रेरणा भी प्रदान करेगी। हमारा लक्ष्य है ड्ड 'हर गाँव सक्षम, हर पंचायत सजग'। नई मार्गदर्शिका में मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की जा रही है, जिसके माध्यम से त्रक्रू का मूल्यांकन, नवीनीकरण और समस्त डाटा डिजिटल रूप से प्रबंधित किया जाएगा। पहली बार ग्राम रोजगार सहायकों को सेवा सुरक्षा और अपील की न्यायसंगत प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही सेवा में अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा, नैतिकता और पारदर्शिता के लिए कठोर प्रावधान किए गए हैं।

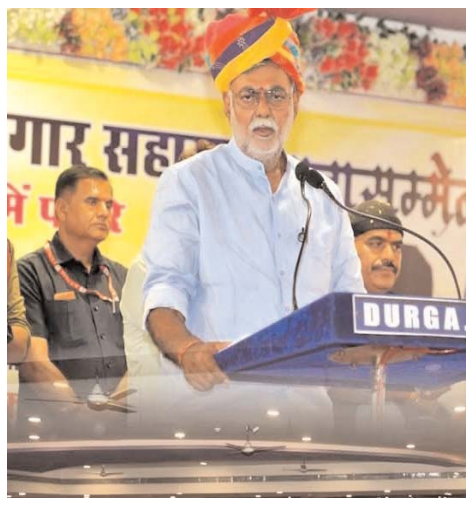

संपादकीय

ट्रंप का 'नोबेल' लालच क्या-क्या करेगा

अमरीका के राष्ट्रपति ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार के लिए इतना क्यों छटपटा रहे हैं? क्या उनके आग्रह पर ही पाकिस्तान ने उनके नाम की सिफारिश की है? क्या यह हास्यास्पद नहीं है कि जिस देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है और सेना ही सरकार को हांकती है, जिस देश को आतंकवाद की पनाहगाह माना जाता रहा है, जो देश पैसा लेकर किसी भी देश के खिलाफ 'जेहाद' करता रहा हो, जिस देश का रक्षा मंत्री कबूल करता हो कि हमने 30 साल में आतंकियों को पाला-पोसा है, उस देश ने नोबेल शांति पुरस्कार राष्ट्रपति ट्रंप को देने की सिफारिश की है? क्या राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति, स्थिरता, मानवता, सौहार्द्र के लिए अमूल्य, अतुलनीय प्रयास किए हैं? यदि अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप खुद को नोबेल शांति पुरस्कार के योग्य मानते हैं, तो मध्य-पूर्व में ही, ईरान के इर्द-गिर्द, अमरीका के 16 बड़े सैन्य अड्डे क्यों हैं? करीब 60 एकड़ क्षेत्र में घातक, संहारक विमान और 51,000 से अधिक सैनिक क्यों तैनात हैं? क्या यह भी शांति के लिए बंदोबस्त किया गया है? कमोबेश अमरीका की सीमाएं वहां से काफी दूर हैं। यह अमरीका का साम्राज्यवाद ही है। बुनियादी तौर पर अमरीका हिंसक, युद्धोन्मादी, जनसंहारक देश है। राष्ट्रपति ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने रवांडा-कांगो के बीच समझौता करवा दिया है, जो सोमवार से प्रभावी हो जाएगा। मिस्र और इथियोपिया में शांति स्थापित कराई है। कोसोवो और सर्बिया के बीच युद्ध रुकवाया है। उन्होंने 15वीं बार यह दावा भी किया है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालिया संघर्ष को खत्म कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पाकिस्तान ने भी अपनी सिफारिश में लिखा है कि भारत के साथ संघर्ष में राष्ट्रपति ट्रंप का हस्तक्षेप एक वास्तविक शांतिदूत के रूप में उनकी भूमिका और बातचीत के माध्यम से संघर्ष के समाधान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह पूरी तरह गलत प्रमाणपत्र है। भारत ने पाकिस्तान के साथ कब बातचीत की थी? सैन्य अफसरों का संवाद युद्धविराम के लिए महज औपचारिकता था। नोबेल पुरस्कार कमेटी को ऐसी छद्म और फर्जी सिफारिश करना ही अपराध है। राष्ट्रपति ट्रंप का नोबेल पुरस्कार के लिए दर्द बार-बार बयां हो रहा है कि वह कितना, कुछ भी कर लें, लेकिन उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार क्या मिलेगा। उनकी यह छटपटाहट इसलिए भी घनीभूत होती है, क्योंकि 2009 में तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। अब यह तय होना है कि ट्रंप पात्र हैं या नहीं?

यादों में आपातकाल

इंदिरा की जेल में नेता, गुंडे, गिरहकट एक भाव!

-जयराम शुक्ल

पंद्रह अगस्त, छब्बीस जनवरी यदि सरकारी आयोजन न होते तो पब्लिक इन्हें कब का भुला चुकी होती। लेकिन कुछ ऐसी तिथियां हैं जिन्हें राजनीति तब तक भूलने नहीं देगी जब तक कि इस देश का अस्तित्व है। इन तारीखों में सबसे ऊपर है 25 जून 1975। इस दिन देश में आपातकाल घोषित किया गया था।

आपातकाल पर मेरे दो नजरिए हैं, एक- जो मैंने देखा, दूसरा जो मैंने पढ़ा और सुना। चलिए पहले से शुरू करते हैं। वो स्कूली छुट्टी के दिन थे, मैं गाँव की स्कूल से सातवीं पास कर आठवीं में जाने के लिए तैयार हो रहा था। 25 जून को गांव में खबर पहुँची कि मीसाबंदी हो गई। शाम को लोग चौगोला बनाकर रेडियो के पास बैठकर खबरें सुनते कि इंदिरा जी ने क्या कहा..। मुझे जहाँ तक याद है, इंदिरा जी ने कहा था कि देश आंतरिक संकट से जूझ रहा है, कुछ विघटनकारी शक्तियाँ देश को बरबाद करने के लिए तुली हैं इसलिए अब संयम और अनुशासन का समय आ गया है।

दूसरे दिन से खबरें आना शुरू हो गई कि पुलिस ने गुंडों की धरपकड़ शुरू कर दी है। हमारे इलाके के कई नामी गुंडे पकड़कर जेल भेज दिए गए। कई व्यापारियों, जमाखोरों के यहां भी छापे पड़े। पुलिस उन्हें पकड़कर थाने ले गई। इमरजेंसी की जिस तरह से शुरुआत हुई गांव-शहर के लोगों ने अमूमन स्वागत ही किया।

सरकारी मुलाजिम समय पर दफ्तर जाने लगे, मास्टर स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने लगे। अपने गांव के ही दो सरकारी मुलाजिम जो शहर में दफ्तर में बाबू थे, दस-दस रुपए की घूस लेते हुए पकड़े गए और मुअत्तल कर दिए गए। मीसा की दहशत का आलम यह था कि खेतों में काम करने वाले हरवाह भी पूरे वक्त मेहनत करते क्योंकि उनके किसान मालिक यह कहते हुए धमकाते थे कि कामचोरी करोगे तो पुलिस मीसा में बंद कर देगी। गांव से शहर जाने वाली बसें इतनी पाबंद हो गईं कि उनके आने-जाने पर आप घड़ी मिला लें।

कुलमिलाकर इमरजेंसी की जो पहली छाप पड़ी वह पटरी से उतरी व्यवस्थाओं को ठीक करने की थी। हां गांव में

यह खबरें आ ही नहीं पाती थीं कि कहां से किस नेता को, किस गुनाह में गिरफ्तार किया गया। गांव के आसपास रहने वाले छुटभैया नेताओं के यहां जब पुलिस पूछताछ के लिए या गिरफ्तार करने पहुँचती तो जरूर चर्चा शुरू होती कि मीसा तो गुंडों को पकड़ने के लिए है लेकिन नेताओं को क्यों पकड़ा जा रहा है। गाँव की चौपालों में शुरू हुई फुसफुसाहट बाद में चर्चाओं में बदल गई कि इंदिरा जी अपने और अपनी पार्टी के विरोधियों को भी ठिकाने लगा रही हैं।

दूसरे नेता थे यमुनाप्रसाद शास्त्री। वे सिरमौर से अपने ही शिष्य काँग्रेसी युवा राजमणि पटेल के हाथों चुनाव गँवा चुके थे। शास्त्री जी की एक आँख गोवा में पुर्तगालियों के दमन में ही जा चुकी थी दूसरी आँख में भी तकलीफ शुरू हो चुकी थी, उसका इलाज चल रहा था, इसलिए वे गिरफ्तारी से बचे रहे। शास्त्रीजी बीमारी हालत में भी आपातकाल के खिलाफ सक्रिय थे। उनके गृहगाँव सूरा का घर अंडरग्राउंड फरारी काट रहे नेताओं की शरणस्थली रहा। कम लोगों को ही मालूम होगा कि 74-75 में नेपाल के प्रमुख नेता गिरजाप्रसाद कोयराला का पूरा परिवार सूरा में ही शरण लिए हुए था। नेपाल में भी भारत जैसे हालात थे।

आपातकाल की गिरफ्तारी में पूरा समाजवाद था, नेता, गुंडे, चोर-उचक्के, कालाबाजारिए सभी जेल में एक भाव थे। बाद में उनमें से कइयो में ऐसा ट्रॉंसफार्मेशन हुआ कि वे जेल तो गए गुंडे के रूप में निकले नेता बनकर। जिन्हें बाद में टिकट भी मिली और वे फिर नेता बन गए। आज उन सबों को केंद्र व राज्य सरकारें अच्छा खासा पेंशन दे रही हैं।

बहरहाल एक दिन गांव में खबर फैली की रीवा सेंट्रल जेल में गोली चली है और सबके सब मीसाबंदी मार डाले गए। खबर की पुष्टि का कोई आधार भी नहीं था। अखबार साफ-साफ कुछ नहीं लिखते थे। धीरे-धीरे खबर साफ हुई कि जेल में रीवा कलेक्टर धर्मेंद्रनाथ को मीसाबंदियों ने लात जूतों से जमकर पिटाई की। वजह यह कि कलेक्टर ने जेल में अव्यवस्थाओं को लेकर अनशन पर बैठे समाजवादी नेता कौशल प्रसाद मिश्र के साथ बदसलूकी कर दी जिससे गुस्सा कर उनके अनुयायियों ने कलेक्टर की पिटाई कर दी थी।

भला हो उस एसपी का जिसने गोली चलाने के कलेक्टर के आदेश को मानने से मना कर दिया वरना गांव में पहुँची कत्लेआम की वह खबर बिल्कुल ही सच साबित होती। बहरहाल लगभग सभी मीसाबंदियों को कड़ी यातनाएं दी गई। रात को कंबल परेड हुई, दूसरे दिन दुर्दांत अपराधियों की तरह आडा-बेडी लगाकर प्रदेश की दूसरी जेलों में शिफ्ट किया गया। इस घटना का पूरा ब्योरा 1978 में रीवा के ऐतिहासिक व्येंकटभवन में तब सुनने को मिला जब यहां इमरजेन्सी के जुल्मों की सुनवाई करने शाह कमीशन आया था।

संजय गाँधी के पाँच सूत्रीय कार्यक्रम कलेक्टरों के लिए ब्रह्मवाक्य की तरह थे। नसबंदी भी एक सूत्र था। इस सूत्र ने देशभर के हजारों, लाखों कुँवरों और बे औलादों की नसबंदी करवा दी। एक भय का माहौल पैदा हो गया कि किसी को पकड़कर कहीं भी नसबंदी की जा सकती है। इमरजेंसी को इस सूत्र ने आम जनता के बीच सबसे ज्यादा बदनाम किया। मेरा मानना है कि यदि नसबंदी कार्यक्रम को जनजागरण के साथ तरीके से व्यवहार में लाया जाता तो आम जनता तमाम स्थितियों के बाद भी इंदिरा जी के साथ खड़ी होती। उसे नेताओं की गिरफ्तारी और प्रेस सेंसरशिप से भला क्या लेना देना..। दफ्तर में घूस बंद थी, सब समय पर हो रहा था, रेल बसें टाइम से चलती थीं, गुंडों सरहंगों का भय खत्म था, बनिये लूटने और मिलावटखोरी से डरने लगे थे। प्रारंभ में आम जनमानस में इमरजेंसी ने कुलमिलाकर यही प्रभाव छोड़ा था। ऊपर से लेकर नीचे तक काँग्रेस के नेता मस्त थे कि जनता उनके साथ है। अखबार उनकी पार्टी की सरकार की जयजयकार कर रही है। देवकांत बरुआ का नारा 'इंदिरा इज इंडिया' चौतरफा गूँज रहा था। कांग्रेस की बड़ी रैलियां और सभाएं होतीं। वही भीड़ अखबारों में छपती पर वो भीड़ कहाँ से जुटती थी नौवीं पढ़ते हुए यह मेरी अपनी आप बीती थी।

यादों में आपातकाल
(भाग दो कल के अंक में पढ़िये)..

आपातकाल की बड़ी भारी हथकड़ी और कोमल कलाई

संतोष शर्मा
आपातकाल के 50 वर्ष

देश मे आपातकाल लगाए जाने वाले काले 25 जून पर प्रतिवर्ष कुछ न कुछ लिखना मेरा प्रिय शगल रहा है। किंतु, आज जो मैं आपातकाल लिख रहा हूं, वह संभवतः इमर्जेंसी के सर्वाधिक कारुणिक कथाओं मे से एक कथा होगी।

जिस देश मे मतदान की आयु शर्त 18 वर्ष हो व चुनाव लड़ने की 21 वर्ष हो वहां 14 वर्ष के अबोध बालक को राजनैतिक अपराध में जेल में डाल देना कौतूहल के साथ साथ क्रोध व कड़वाहट उत्पन्न करता है। किंतु इस देश मे यह भी सत्य हुआ आपातकाल के दौर मे। वैसे जिन बंधुओं ने इमर्जेंसी की भयावहता बताने वाली, विनोद मेहता की पुस्तक ÷द संजय स्टोरी÷ पढ़ी होगी उन्हे आपातकाल की यह करुणापूर्ण कथा ÷द संतोष शर्मा स्टोरी÷ पढ़कर कोई आश्चर्य नहीं होगा।

इंदिरा गांधी द्वारा लिखा और उनके पुत्र संजय गांधी द्वारा क्रियान्वित किया गया आपातकाल का अध्याय स्वतंत्र भारत का सर्वाधिक भयावह, भ्रष्ट व भद्दा भाग है। 25 जून 1975 की रात्रि अचानक ही इंदिरा गांधी व उनके कानून मंत्री सिद्धार्थशंकर रे ने देश मे आपातकाल लागू करने का मसौदा बनाया, आधी रात्रि को देश के महामहिम राष्ट्रपति फख़रुद्दीन अली अहमद को सोते से उठाकर पढे-अनपढ़े ही हस्ताक्षर कराई गई और देश को आपातकाल के आततायी कालखंड मे धकेल दिया गया। इंदिरा जी तो नाममात्र की प्रधानमंत्री रह गई और देश की बागडोर संजय गांधी व उनकी रुखसाना सुलताना जैसी चांडाल चौकड़ी के हाथों मे आ गई। आश्चर्य है कि आपातकाल के इस डरावने दौर मे इंदिरा जी के मंत्री देवकांत बरुआ जैसे चमचों ने 'इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा' का बेसुरा राग भी अलापा था। 25 जून 1975 को लगाए गए इस आपातकाल के बहुत से स्याह और बदनाम पहलू हैं किंतु आज यहां एक बालक की गिरफ्तारी की चर्चा की जा रही है जिसे आपातकाल के दौरान बरती गई असंवेदनशीलता व निर्ममता की प्रतिनिधि घटना के रूप मे लिया जा सकता है।

संतोष जी शर्मा बचपन से राष्ट्रवादी विचारधारा के धनी थे। पिता भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी थे सो पारिवारिक वातावरण ही संघमय था। इस बाल स्वयंसेवक के साथ हुआ कुछ इस तरह कि आपातकाल लगने के बाद संतोष जी शर्मा जो उस समय नवमी कक्षा मे शिक्षारत थे ने अपने वरिष्ठ साथियों सुरेश शर्मा, अशोक गर्ग,शंभू सोनकिया, चन्द्रभान जी, रमेश सिंह जी आदि के साथ भोपाल के चौक पर आपातकाल विरोधी प्रदर्शन किया। बस प्रदर्शन करने की देर थी कि कुछ ही समय मे पुलिस आई और सभी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करके ले गई।अब यह बात अलग थी कि उन 15 डंडों ने संतोष कुमार शर्मा का चेहरा, चाल, ढाल सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया था। खैर, संतोष शर्मा ने इस सबके बाद भी पुलिस के सामने क्षमा मांगने से इंकार कर दिया और परिणामस्वरूप वे अपने सभी साथियों के साथ भोपाल जेल भेज दिये गए। भोपाल जेल भेजें जाने के दौरान सभी को हथकड़ियां पहनाई गई, किंतु जब संतोष शर्मा के छोटे से शरीर की छोटी-छोटी कलाई मे हथकड़ी पहनाने की बात आई तो पता चला कि उसके नाप की तो हथकड़ी ही जेल प्रशसान के पास नहीं है। जो हथकड़ी संतोष शर्मा को पहनाई जाती उससे संतोष की कलाई तुरंत ही फिसलकर बाहर आ जाती। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद तो जैसे संघर्ष का दोहरा दौर प्रारंभ हो गया। पाठशाला से नाम काट दिया गया। अन्य विध्यालयों मे चक्कर मारे किंतु कोई प्रवेश देने को तैयार ण हुआ। सहपाठी, मित्र आदि सभी कन्नी काटने लगे व इंदिरा शासण के भय से इस अबोध बालक से दूरी बनाकर रखने लगे। अब पढ़ाई से तो कुछ समय के लिए संबंध टूट गया और मानस मे राष्ट्रवाद और आपातकाल का विरोध बसा ही था सो संतोष ने अपने लिए एक काम तलाश लिया और मीसा बंदियों और उनके संघर्षरत परिवारों के लिए काम करने लगे। मीसाबंदियों के परिवारों के लिए संगठन के अन्य लोगों के साथ चंदा एकत्रित करते, आटा इकट्ठा करते और उसे प्रत्येक परिवारों तक पहुंचाते।

आपातकाल के पचास साल

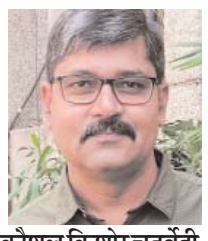

कौशल किशोर चतुर्वेदी

भारत के राजनीतिक इतिहास में 25 जून की तारीख एक काले अध्याय के रूप में ही दर्ज है। 25 जून 1975 को भारत में तीसरे आपातकाल की घोषणा की गई थी। इस आपातकाल को सत्ता के परम वैभव को चुनौती देने वाली न्यायपालिका, विपक्ष, मीडिया और देश के हर नागरिक को प्रताड़ित करने के रूप में देखा जाता है। न्यायपालिका ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1971 में रायबरेली से लड़े गए चुनाव को रद्द कर दिया था और उन्हें 6 साल तक चुनाव लड़ने से रोक दिया था। और इस फैसले के खिलाफ आयरन लेडी इंदिरा गांधी लोहे की तरह कठोर होकर गरजी थी और आपातकाल लगाने के साथ संविधान संशोधन कर तत्कालीन सरकार ने न्यायपालिका को सीमित कर दिया था। मीडिया पर कड़ा प्रहार किया गया था। विपक्षियों से जेलें भर गई थीं। और नसबंदी अभियान चलाकर देश के हर नागरिक के मन में प्रताड़ना और भय का माहौल बना दिया था। आज अगर कांग्रेस संविधान बचाओ की बात कर रही है तो 1975 से 1977 तक विपक्षी दल भी इंदिरा सरकार पर संविधान की हत्या का आरोप लगा रहे थे। और विपक्ष के यह आरोप आज भी जिंदा हैं। हालांकि कांग्रेस आज भी आपातकाल के उस दौर को तर्कसंगत ठहरने की कोशिश कर सकती है और वर्तमान भाजपा सरकार की कमियों को गिनाने की हकदार है। और 25 जून 2025 को आपातकाल के 50 साल पर कम से कम भाजपा और कांग्रेस के बीच वाद-विवाद की ऐसी स्थितियां कोई आश्चर्य की बात नहीं हैं। पर इसे राजनीति की विडंबना ही माना जाएगा और राजनेताओं की इस मजबूरी को राज सिंहासन से बंधे भीष्म पितामह की मजबूरी की तरह ही देखा जाएगा। पर 1977 के चुनाव में देश के नागरिकों ने आयरन लेडी इंदिरा गांधी को आइना दिखा दिया था। और देखा जाए तो इंदिरा का वह अड़ियल रवैया ही कांग्रेस की पहली बड़ी हार की वजह बना था। तब आपातकाल के बाद देश ने पहली गैर कांग्रेसी सरकार देखी थी। तब से अब तक के 50 साल में गैर कांग्रेसी सरकारों का लंबा दौर हो चुका है। और पिछले 11 साल से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार कांग्रेस को आइना दिखा रही है। खैर 25 जून 2025 को उस तीसरे आपातकाल के 50 साल पूरे हुए हैं जिसकी आलोचना हर स्तर पर होती रही है। हालांकि इससे पहले भी युद्ध

की वजह से देश दो बार आपातकाल देख चुका था लेकिन तब हर भारतवासी कांग्रेस सरकार के साथ खड़ा दिखाई दिया था। आइए हम आपातकाल और इन तीनों आपातकालों के बारे में जानते हैं।

आपातकाल सम्पूर्ण देश या फिर किसी भी राज्य की वह असंतुलित स्थिति है जिसमें संवैधानिक और प्रशासनिक संतुलन छिन्न भिन्न हो जाते हैं। भारत के संविधान में राष्ट्रपति की कुछ शक्तियों के बारे में लिखा गया है–कि राष्ट्रपति कब किस तरह की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। उन्हीं शक्तियों में से एक शक्ति आपातकाल की है। जब सम्पूर्ण देश या किसी राज्य पर अकाल, बाहरी देशों के आक्रमण या आंतरिक प्रशासनिक अव्यवस्था आदि की स्थिति आती है तो उस समय उस क्षेत्र की सभी राजनैतिक और प्रशासनिक शक्तियाँ राष्ट्रपति के हाथों में चली जाती हैं। पहला आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 के बीच भारत चीन युद्ध के दौरान लगा था, जब ÷भारत की सुरक्षा÷ को ÷बाहरी आक्रमण से खतरा÷ घोषित किया गया था। दूसरा आपातकाल 3 से 17 दिसंबर 1971 के बीच भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान घोषित किया गया था। और आपातकाल की तीसरी उद्घोषणा इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में 25 जून 1975 को देश में राजनीतिक अस्थिरता की विवादास्पद परिस्थितियों में हुई थी। उन्हें अपने पद पर बने रहने की वैधता को चुनौती देते हुए अगले 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया था। इंदिरा गांधी ने अपना कार्यकाल मजबूत करने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल की घोषणा करने की सिफारिश की थी। आपातकाल की घोषणा के समय समाचार पत्र के मालिक या तो उद्योगपति थे या फिर प्रिंटिंग प्रेस के व्यवसाय से जुड़े लोग। सभी ने सरकारी लाइन का पालन किया। समाचार पत्रों को अगले दिन के संस्करण प्रकाशित करने के लिए मंजूरी मांगनी होती थी। सरकार ने समाचार पत्रों को संपादकीय वाले कॉलम खाली छोड़ने पर भी चेतावनी जारी की थी। इंडियन एक्सप्रेस ने 28 जून 1975 के अपने संस्करण में संपादकीय खाली छोड़ा था। रिपोर्टरों को ध्यान रखना होता था कि सरकार नाराज न हो जाए। मीडिया को लेकर दोनों दल आज भी तुलनात्मक स्थितियों पर खुलकर चर्चा जरूर कर सकते हैं लेकिन तब भी आपातकाल के उस काले अध्याय को तर्कसंगत नहीं ठहराया जा सकता है। देश के उस तीसरे आपातकाल के 50 साल यह संतोष करने के लिए अच्छे हैं कि देश ने फिर वैसा दौर कभी नहीं देखा।

ईरान की सैन्य क्षमता से अब दुनिया में दहशत

डॉ.ब्रह्मदीप अलूने

ईरान-इजराइल संघर्षविराम होने से मध्यपूर्व में फिलहाल शांति कायम होने की उम्मीदें भले ही बढ़ गई है लेकिन इस दौरान ईरान ने अपनी सैन्य ताकत का जो दुनिया का सामने प्रदर्शन किया है, वह बेहद खतरनाक है। इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस-3 नामक ईरान के अभियान के दौरान उपयोग किए गए अत्याधुनिक हथियारों और उच्च निर्देशित मिसाइलों से यह साफ हो गया है कि वैश्विक प्रतिबंधों से इस शिया देश पर कोई फर्क नहीं पड़ा है और संयुक्त राष्ट्र उसकी सैन्य भागीदारियों को रोकने में नाकाम रहा है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इजराइल और अमेरिका के ठिकानों को जिस मजबूती से निशाना बनाया है, उससे मध्यपूर्व के अन्य देशों में भी दहशत बढ़ गई है।

इजराइल के डिफेंस सिस्टम का लोहा पूरी दुनिया मानती है। आयरन डोम इजराइल का सबसे चर्चित डिफेंस सिस्टम है, जो आजमाया और सफल माना जाता था। इसे 4 किलोमीटर से 70 किलोमीटर की दूरी तक दागे गए कम दूरी की रॉकेटों, गोले और मोर्टार को गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। आयरन डोम मिसाइल डिफेन्स सिस्टम रडार के जरिए आने वाली रॉकेटों को पहचानता और ट्रैक करता है और ये तय करता है कि कौन-सी रॉकेट आबादी वाले इलाकों पर गिर सकती है। ईरान ने इजराइल पर 450 से अधिक मिसाइलें और 1000 ड्रोन दागे। इसमें कई मिसाइलें रिहायशी इलाकों में गिरी और इजराइल को भारी नुकसान हुआ।

हाइफा इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, जो आर्थिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इंटेल जैसी हाईटेक कंपनियों के दफ्तर हाइफा में मौजूद हैं। हाइफा में इजराइल की सबसे बड़ी ऑइल रिफाइनरी है। इस रिफाइनरी पर हमला करके ईरान से इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था को भेदने में बड़ी सफलता हासिल की। हाइफा और तेल अवीव जैसे शहरों की घनी आबादी है और वो इजराइली अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। इन दोनों शहरों पर ईरानी मिसाइलें गिरी। आयरन डोम को इजराइली कंपनी राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स और इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने अमेरिकी सहयोग के साथ विकसित किया था। इसे 2011 से इजराइल की रक्षा कर रहे इस सिस्टम को भेदकर ईरान से यह बता दिया है कि कोई भी सुरक्षा सिस्टम फूलप्रूफ नहीं हो सकता। ईरान-इजराइल संघर्ष में उन्नत मिसाइलों का इस्तेमाल कर ईरान ने यह भी बता दिया है कि उसकी सैन्य क्षमताओं को कमतर आंकने की गलती अब दुनिया नहीं कर सकती। मिसाइल प्रौद्योगिकी की ईरानी खरीद पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों और मिसाइल विकास में शामिल संस्थाओं पर प्रतिबंधों का ईरान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इस समय ईरान के पास मध्य- पूर्व में सबसे बड़ा और सबसे विविध मिसाइल शस्त्रागार है जिसमें हजारों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं, जो इजराइल और दक्षिण-पूर्वी यूरोप तक हमला करने में सक्षम हैं।

इससे यह भी साफ हो गया की ईरान लाल सागर और फारस की खाड़ी में ड्रोन, मिसाइलों और बारूदी सुरंगों से जहाजों और बंदरगाहों पर हमला करके वैश्विक तेल जगत के

एक प्रमुख मार्ग को बाधित करने की ईरान की क्षमता को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज में इराक, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, जॉर्डन और सीरिया में अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं। अमेरिका के ईरान ने कतर स्थित अल-उदीद अमेरिकी सैन्य हवाई अड्डे पर ताकतवर और विनाशकारी हमला कर अमेरिका को यह संदेश दे दिया कि उसकी सैन्य क्षमताएं कितनी मजबूत है। यह बेस अमेरिकी एयरफोर्स का हेडक्वार्टर है और पश्चिमी एशिया पर वह यहीं से नजर रखता है।

ईरान की कई मिसाइलें स्वाभाविक रूप से परमाणु पेलोड ले जाने में सक्षम हैं, जो अंतरराष्ट्रीय चिंता का विषय होना चाहिए। ईरान ने यमन के हूथी विद्रोहियों जैसे प्रॉक्सी को भी मिसाइलें हस्तांतरित की हैं जिन्होंने सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में नागरिक लक्ष्यों पर हमला करने के लिए और लाल सागर से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों को परेशान करने के लिए उनका इस्तेमाल किया है।

ईरान ने 2015 में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि उसके पास 2,000 किलोमीटर तक मार करने वाली अत्याधुनिक मिसाइलें है। ईरान ने फत्ताह-1 को हाइपरसोनिक मिसाइल बताया है। ईरान के पास खेबर शेकन एक बहु-युद्धक बैलिस्टिक मिसाइल है। खेबर शेकन, ईरान की सबसे उन्नत लंबी दूरी की मिसाइल तकनीकों में से एक है। यह मिसाइल पश्चिमी ईरान से इजराइल तक पहुंचने में सक्षम है। यह बढ़ी हुई सटीकता के लिए एक उपग्रह-निर्देशित प्रणाली और युद्धाभ्यास योग्य वारहेड का उपयोग करने में सक्षम है।

1979 में ईरानी क्रांति के बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ विभिन्न आर्थिक, व्यापार, वैज्ञानिक और सैन्य प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों का ईरान की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ा। 1979 की ईरानी क्रांति के बाद से मुस्लिम दुनिया का ईरान के साथ रिश्ता खराब रहा है। प्रथम खाड़ी युद्ध से लेकर सुन्नी-शिया विभाजन तक तेहरान और उसके खाड़ी पड़ोसियों के बीच मौलिक मतभेद मौजूद हैं। 1984 में अमेरिकी विदेश विभाग ने ईरान को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी गतिविधियों के लिए समर्थन देने के लिए आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला देश घोषित किया था। इस घोषणा के साथ ही उस पर व्यापक अमेरिकी प्रतिबंध भी लगाए गए थे। 2008 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 1803 पारित किया। इससे ईरान पर परमाणु संबंधी प्रतिबंधों का विस्तार हुआ। 2013 में अमेरिकी कांग्रेस ने ईरान स्वतंत्रता एवं प्रसाररोधी अधिनियम के तहत ईरान में कारोबार करने वाली कंपनियों के खिलाफ प्रतिबंधों के खतरे को और बढ़ा दिया।

करीब ढाई दशक पहले ईरान ने अवैध रूप से 6 सोवियत निर्मित एयर लॉन्च क्रूज मिसाइलें हासिल की थीं जिनकी रेंज 2,500 किलोमीटर तक बताई जाती थी। अब ईरान बहुत आगे बढ़ गया है। दुनिया को यह भी चिंता है कि जो देश आतंकी समूहों को बैलिस्टिक मिसाइलें दे सकता है, वह मौका आने पर परमाणु हथियार भी दे देगा। ईरान के हुती विद्रोही सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात पर हमले कर चुके हैं।

ईरान और उसके धार्मिक नेता के इरादे धार्मिक उन्माद के जरिए सांस्कृतिक टकराव बढ़ाने वाले रहे हैं। ईरान के परमाणु ठिकानों को खत्म करने के अमेरिका और इजराइल के अभियान को यूरोप और मध्य-पूर्व के कई देशों का समर्थन हासिल है। हालांकि ईरान को रोकना बेहद कठिन है, क्योंकि रूस और चीन जैसी शक्तियां उसके साथ हैं, जो अंतरराष्ट्रीय नियमों की परवाह नहीं करतीं। बहरहाल, दुनिया को यह समझना होगा कि यदि ईरान को रोका नहीं गया तो इसके वैश्विक प्रभाव बेहद विध्वंसक हो सकते हैं।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक भरत पटेल द्वारा इंडिपेंडेंट प्रेस 11, प्रेस काम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल से मुद्रित तथा 226, एमपी नगर जोन-2, भोपाल से प्रकाशित। संपादक — भरत पटेल, प्रबंध सलाहकार — भारती पटेल, संपादकीय सलाहकार — विष्णु कौशिक, सलाहकार संपादक - स्मिता पटेल, स्थानीय संपादक —हाकम सिंह गुर्जर
प्रकाशन से संबंधित समस्त समाचार चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार। समस्त न्यायिक कार्यवाहियों के लिए क्षेत्राधिकार भोपाल न्यायालय का रहेगा। रजि. नं. भोपाल डिवी. 48 म. प्र. ई-मेल : dspbpl67@gmail.com, वेबसाईट: dainiksandhyaprakash.in

एमपीएल-2025 : रोमांचक फाइनल में भोपाल ने चंबल घडियाल को हराया, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सपरिवार पहुंचे

ग्वालियर के श्रीमंत माधवराव सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड में मंगलवार को एमपीएल 2025 का फाइनल मैच भोपाल और चंबल के बीच खेला गया। इस मैच को लेकर ग्वालियर के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मुख्य अतिथी के तौर पर समापन समारोह में शामिल हुए। ग्वालियर के माधवराव सिंधिया इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग 2025 के फाइनल मुकाबलों ने क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह दोगुना कर दिया। फाइनल में भोपाल लेपर्ड्स ने चंबल घड़ियाल को दो रन से हरा दिया है। केंद्रीय संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने पुरुष वर्ग के फाइनल मुकाबले में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जहां उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने समापन समारोह में खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग न केवल एक खेल आयोजन है, बल्कि यह हमारे युवाओं को राष्ट्रीय मंच पर ले जाने का एक मंच है। साथ ही प्रदेश की बेटियों के लिए भी गर्व का क्षण है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महानारायमण सिंधिया, जो GDCA के उपाध्यक्ष और MPLT20 के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी इस आयोजन की सफलता पर खुशी जताई और कहा कि यह लीग स्थानीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएगी। इस टूर्नामेंट ने न केवल पुरुष क्रिकेट को नई ऊंचाइयां दीं, बल्कि पहली बार शामिल हुई महिला क्रिकेट लीग ने भी इतिहास रच दिया। चंबल घड़ियाल्स ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शानदार प्रदर्शन कर दबदबा कायम किया। 12 जून से 24 जून 2025 तक माधवराव सिंधिया इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित इस टूर्नामेंट ने मध्य प्रदेश को क्रिकेट के नक्शे पर एक नई पहचान दी है। यह स्टेडियम अब प्रदेश के उभरते खिलाड़ियों के लिए एक प्रमुख केंद्र बन चुका है।

आंबेडकर की मूर्ति लगाने में भाजपा राजनीति कर रही है: उमंग सिंघार

जबलपुर। मध्यप्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार मंगलवार को जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर मीडिया को संबोधित किया। मीडियाकर्मियों से चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला।

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सबसे पहले वीरांगना रानी दुर्गावती जी के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन किया। इसके बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पेड़ भाजपा सिर्फ पेपर पर लगाती है। उन्होंने कहा कि नर्मदा नदी के किनारे पेड़ लगाने के नाम पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी ने ?350 करोड़ का घोटाला किया था। जब भाजपा सरकार नर्मदा मईया को नहीं छोड़ रही तो जनता को क्या बख्शेगी।

नेता प्रतिपक्ष ने जबलपुर के मुद्दों पर बात करते हुए कहा कि महाकौशल में ना तो उद्योग लग रहे हैं और ना ही यहां के युवाओं को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि यहां धान की पैदावार भी अच्छी होती है लेकिन धान किसानों के लिए कब सोचेगी भाजपा सरकार?

उन्होंने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार धान किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान भुगतान की बात करती है मगर अब तक नहीं दिया गया।

उमंग सिंघार ने कहा कि भाजपा की मंशा साफ है वो कालाबाजारी करना चाहती है, मगर किसानों को उनके अधिकार नहीं देना चाहती। वहीं महिला सुरक्षा के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रदेश का गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री जी के पास है फिर भी प्रदेश में महिला सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। जो अधिकारी काम के नहीं है उन्हें ब्लाक्त भेजा जाए और बेहतर अधिकारियों को सुरक्षा का जिम्मा दिया जाए।

नेता प्रतिपक्ष ने अंत में कहा कि भाजपा हमेशा सिर्फ धर्म की बात करती है। आज यही कारण है कि बाबा साहेब की मूर्ति लगाने में भाजपा राजनीति कर रही है। ये वही पार्टी है जो संविधान खत्म करना चाहती है। मीडिया और आम लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि महान विभूतियों को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रदेश में विकास कैसे होगा इसपर बात होनी चाहिए।

मध्यप्रदेश में मूंग-उड़द एमएसपी खरीद को लेकर समीक्षा बैठक,

कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने कहा, किसानों से निष्पक्ष होगी खरीदी

भोपाल। कृषि की अध्यक्षता में हुई बैठक में खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और किसान हितैषी बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई। मंत्री कंसाना ने कहा कि किसानों से बिना किसी भेदभाव के खरीदी की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को पर्याप्त उपार्जन केंद्र स्थापित करने, समय पर तुलाई और भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मध्यप्रदेश में मूंग और उड़द की समर्थन मूल्य पर खरीदी को लेकर कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में खरीदी व्यवस्था को निष्पक्ष, पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के नेतृत्व में किसानों के लिए लाभकारी नीतियां बनाई जा रही हैं।

ऐदल सिंह कंसाना ने केंद्र और राज्य सरकार के नेतृत्व के प्रति आभार जताया और कहा कि खरीदी प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष होगी तथा किसानों से बिना किसी भेदभाव के उपज खरीदी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए पर्याप्त संख्या में उपार्जन केंद्र स्थापित किए जाएं।

प्रदेश में मूंग की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की पारदर्शिता और सुचारू संचालन को लेकर आज भोपाल में एक अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने की। बैठक के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों से बिना किसी भेदभाव के खरीदी की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पर्याप्त संख्या में उपार्जन केंद्र स्थापित किए जाएं ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। साथ ही, समय पर तुलाई और भुगतान सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

जारी है पंजीयन प्रक्रिया

बता दें कि मूंग और उड़द की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए पंजीयन प्रक्रिया 19 जून से शुरू हो चुकी है। पंजीयन कराने की अंतिम तिथि 6 जुलाई है। उपार्जन कार्य 7 जुलाई से 6 अगस्त तक चलेगा। इस बार मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 8682 रुपये प्रति क्विंटल और उड़द का 7400 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। किसान समग्र पोर्टल या नजदीकी कृषि उपज मंडियों में पंजीयन करा सकते हैं। सिर्फ पंजीकृत किसान ही एमएसपी योजना का लाभ उठा सकेंगे।

ग्वालियर से बैंगलुरु के लिये नई रेल सुविधा 26 जून से

प्रभारी मंत्री एवं ऊर्जा मंत्री ने रेलवे स्टेशन पहुँचकर अधिकारियों से की चर्चा

ग्वालियर। ग्वालियर वासियों के लिये भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा गाड़ी संख्या 11086/85 ग्वालियर से बैंगलोर (बैंगलुरू) के लिये 26 जून 2025 को प्रारंभ की जा रही है। इस नई रेल सुविधा से आईटी के क्षेत्र में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को ग्वालियर से सीधे बैंगलोर जाने के लिये बेहतर सुविधायें उपलब्ध होंगीं।

प्रदेश के जल संसाधन मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, ऊर्ज मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मंगलवार को ग्वालियर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नं.-4 पर पहुँचकर नई रेल सुविधा के संबंध में रेलवे विभाग के अधिकारियों से चर्चा की। उनके साथ भाजपा जिला अध्यक्ष श्री जयप्रकाश राजौरिया सहित रेलवे के अधिकारी व जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

प्रभारी मंत्री श्री सिलावट एवं ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने ग्वालियर से बैंगलोर के लिये प्रारंभ हो रही नई रेल सुविधा के संबंध में जानकारी प्राप्त की। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि 26 जून को ग्वालियर रेलवे स्टेशन से नई रेल को हरी झण्डी दिखाकर समारोहपूर्वक रवाना किया जायेगा।

रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर राज्यमंत्री एवं सांसद ने सिंग्रामपुर में किया माल्यार्पण

दमोह। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे विधानसभा जबेरा के सिंग्रामपुर में रानी दुर्गावती जी ने राज किया और हम सभी की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। रानी दुर्गावती ने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए उनके दांत खट्टे करने का काम किया। रानी दुर्गावती ने एक समाज के लिए नही अपितु सर्वसमाज की रक्षा करने का काम किया, ऐसी महान वीरांगना के चरणों में बारंबार नमन करता हूं। हमारी सरकार निरंतर आदिवासी समाज के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही हैं। इस आशय के विचार प्रदेश के संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक एवं धर्मस्व राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेन्द्र सिंह लोधी ने गोंडवाना साम्राज्य की महान वीरांगना रानी दुर्गावती जी के बलिदान दिवस के अवसर सिंग्रामपुर स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मंचीय कार्यक्रम में व्यक्त किये। इस अवसर पर सांसद राहुल सिंह ने भी वीरांगना रानी दुर्गावती जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। राज्यमंत्री लोधी ने कहा सिंग्रामपुर में एक छोटा सा कार्यक्रम रखकर आदिवासी समाज को सम्मानित करने का भी काम किया। रानी दुर्गावती जी की वीर गाथा सुनाने और बताने का काम हम सबने किया है। मुझे लगता है, रानी दुर्गावती जी का पराक्रम हम सबको प्रेरणा देने का काम करता रहेगा और धरती आबा योजना के अंतर्गत 113 गांव हमने जबेरा जनपद में चिन्हित किये है जिसमे 242 करोड़ की योजना बनाकर केंद्र सरकार को भेजी है। 114 आदिवासी ग्राम हमने तेंदूखेड़ा जनपद में चिन्हित किये है, आदिवासी समाज के उत्थान के लिए हमारी सरकार संकल्पित है और निरंतर हम आदिवासी समाज के उत्थान के लिए काम करते रहेंगे। इस अवसर पर पूर्व जिला पंचायत

अध्यक्ष अनीता सिंह, श्री भावसिंह मासाब, संग्राम सिंह, खड़क सिंह मासाब, राजा भैया, विवेक शाह, सुनील शाह, राजा साहब गुबरा, बंटी दुबे, मंदीप यादव, सतपाल सिंह, रिंकू जैन, संतकुमार पाल, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी, ग्रामीण जन मौजूद थे।

ईवी कंपनी सुपरटेक ईवी की पब्लिक इश्यू से रु. 29.90 करोड़ तक की धनराशि जुटाने की योजना

हरियाणा, एजेंसी। भारतीय इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) बाजार में अग्रणी कंपनीओं में से एक और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स पर ध्यान रख रही सुपरटेक ईवी लिमिटेड अपने एसएमई पब्लिक इश्यू से रु. 29.90 करोड तक जुटाने की योजना बना रही है। कंपनी को बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर अपना पब्लिक इश्यू लॉन्च करने की मंजूरी मिल गई है। पब्लिक इश्यू 25 जून, 2025 को सब्सक्रीप्शन के लिए खुलेगा और 27 जून, 2025 को बंद होगा। कॉर्पोरेट मेकर्स कैपिटल लिमिटेड इस इश्यू की बुक रनिंग लीड मैनेजर है। रु. 29.90 करोड का आईपीओ पूरी तरह से रु. 10 के अंकित मूल्य के 32,49,600 इक्विटी शेयरों का एक फ्रेश इश्यू है। इश्यू के लिए प्राइज बैंड रु. 87 - 92 प्रति शेयर है। इश्यू से प्राप्त राशि में से कंपनी रु. 16.50 करोड कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए, रु. 3 करोड कंपनीने लिए हुए कुछ उधारों के कुछ हिस्से के पुनर्भुगतान के लिए और शेष सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों और इश्यू से संबंधित खर्चों के लिए उपयोग करने की योजना बना रही है। आवेदन के लिए न्यूनतम लॉट साइज 1,200 शेयर है, यानि की रु. 92 प्रति शेयर के अपर प्राइज बैंड पर रु. 1,10,400 का न्यूनतम निवेश करना होगा।

अमेज़न के साथ होमएसेंशियल्स के सफ़र की शुरुआत

मुंबई, एजेंसी। होमएसेंशियल्स की शुरुआत एक मामूली समझ से हुई कि घर और रसोई की ज़रूरी चीज़ें उबाऊ, पुरानी या सिर्फ काम की क्यों होनी चाहिए? संस्थापकों को बाज़ार में एक कमी दिखी कि पारंपरिक ब्रांडों में आधुनिक सौंदर्य और व्यावहारिक खूबसूरती की कमी थी, जो आज के भारतीय उपभोक्ता चाहते हैं। इस कमी को पूरा करने और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने अमेज़न पर होमएसेंशियल्स लॉन्च किया। डिजिटल-फर्स्ट (डिजिटल प्रक्रिया पर केंद्रित) पर आधारित एक एमएसएमई के ?रूप में, होमएसेंशियल्स भारतीय घरों के रोज़मर्रा की चीज़ों को नया स्वरूप प्रदान कर रहा है। इस एमएसएमई दिवस के मौके पर, उनकी कहानी इस बात का प्रमाण है कि अमेज़न जैसे डिजिटल मार्केटप्लेस किस तरह आधुनिक व्यवसायों को बढ़ाने, प्रतिस्पर्धा करने और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नया रंग भरने में मदद कर रहे हैं।

एसीसीए ने अकाउंटेंसी पेशे की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए संशोधित योग्यता का किया अनावरण

मुंबई, एजेंसी। वैश्विक लेखा निकाय, एसीसीए (एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स) ने लेखा (अकाउंटेंसी) पेशे की उभरती और विस्तारित भूमिका के अनुरूप अपनी प्रमुख स्वर्ण मानक योग्यता में बदलाव करने की घोषणा की है।यह नया स्वरूप दिखाता है कि कैसे अकाउंटेंट अब व्यवसायों को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं - न केवल मुनाफ़ा कमाकर, बल्कि नैतिकता, स्थिरता, नई तकनीक और आर्थिक बदलावों को संभालने पर ध्यान केंद्रित कर भी। सार्वजनिक क्षेत्र में भी इसी तरह के बदलाव हो रहे हैं। ये बदलाव नियोक्ताओं की उभरती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं, साथ ही इसमें एसीसीए योग्यता की मौजूदा क्षमता पर भी ध्यान दिया गया है। इसके तहत बेहतर पढ़ाई और मूल्यांकन प्रक्रिया की पेशकश की जाएगी, जिसमें एआई-संवर्धित पढाई भी शामिल है। इसे अगली पीढ़ी को गतिशील और लगातार बदलती दुनिया में सफल होने के लिए आवश्यक पेशेवर कौशल और तकनीकी विशेषज्ञता से लैस करने के लिए तैयार किया गया है।

भारत-ब्रिटेन के बीच जुलाई के अंत तक व्यापार समझौता होने की संभावना कानूनी प्रक्रिया अंतिम चरण में

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को कानूनी रूप देने की प्रक्रिया तेज गति से आगे बढ़ रही है। इस पर जुलाई के अंत तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। मंगलवार को एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। इस प्रक्रिया को गति देने के लिए वाणिज्य सचिव सुनिल बर्थवाल अपनी आधिकारिक टीम के साथ लंदन में हैं। बर्थवाल अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान ब्रिटेन के बिजनेस एंड ट्रेड सेक्रेटरी जोनाथन रेनॉल्ड्स और अन्य वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। भारत और यूके ने 6 मई को एफटीए वार्ताओं को औपचारिक रूप से पूरा करने की घोषणा की। इस समझौते के तहत भारत से चमड़ा, जूते और वस्त्र जैसे श्रम-प्रधान उत्पादों के निर्यात पर शुल्क समाप्त हो जाएगा। वहीं ब्रिटेन से व्हिस्की और कारों का आयात सस्ता होगा। दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच 2030 तक व्यापार दोगुना होकर 120 बिलियन डॉलर हो जाएगा। विश्व की पांचवीं और छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने तीन वर्षों की वार्ता के बाद इस समझौते को संपन्न किया। एफटीए पर हस्ताक्षर के बाद, इसे लागू करने से पहले ब्रिटिश संसद और भारत की केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी लेनी होगी। इसके बाद इसे लागू होने में लगभग एक वर्ष का समय लग सकता है। अधिकारी ने बताया कि एफटीए के कानूनी मसौदे की समीक्षा के लिए भारत की कानूनी टीम भी लंदन में है। समझौते पर हस्ताक्षर के बाद इसका पूरा पाठ सार्वजनिक किया जाएगा। इससे पहले इसी महीने केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी लंदन में थे और उन्होंने एफटीए के कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दों पर जोनाथन रेनॉल्ड्स से चर्चा की थी।

घरेलू शेयर बाजार में हरियाली शुरुआती कारोबार में उछले सेंसेक्स-निफ्टी

मुंबई, एजेंसी। ईरान और इस्राइल के बीच संघर्ष विराम के बाद पश्चिम एशिया में तनाव कम होने के संकेतों के बीच वैश्विक बाजारों में तेजी के चलते बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में बुधवार को शुरुआती कारोबार में तेजी दर्ज की गई। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 426.79 अंक बढ़कर 82,481.90 पर पहुंच गया। 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 123.25 अंक चढ़कर 25,167.60 पर पहुंच गया। फिलहाल सेंसेक्स 550 से ज्यादा और निफ्टी 150 से ज्यादा अंकों की बढ़त के साथ हरे निशान पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स की 30 कंपनियों में टाइटन, एचसीएल टेक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अल्ट्राटेक सीमेंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर और टाटा स्टील सबसे ज्यादा फायदे में दिखीं। ऐसे ही कोटक महिंद्रा बैंक और आईसीआईसीआई बैंक पिछड़ते नजर आए। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 1.30 प्रतिशत उछलकर 68.01 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने मंगलवार को 5,266.01 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 5,209.60 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। रिलायंस सिक्योरिटीज के शोध प्रमुख विकास जैन ने बाजार खुलने से पहले अपनी टिप्पणी में कहा, ईरान और इस्राइल के बीच संघर्ष विराम के बाद भू-राजनीतिक तनाव कम होने, अमेरिकी बाजार चार महीने के उच्चतम स्तर पर बंद होने और कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट के कारण बाजार सकारात्मक रुख के साथ खुलने की उम्मीद है। पिछले कुछ दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में 15 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है, जो 5 महीने के निचले स्तर 68 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गई है।

चीन के ठेंगा दिखाने के बाद जागी सरकार, अब देश में ही होगा रेयर अर्थ मैग्नेट का उत्पादन

नई दिल्ली, एजेंसी। चीन ने भारत को रेयर अर्थ मैग्नेट देने से इनकार कर दिया है। इसके बाद अब देश में ही इनके उत्पादन का इंतजाम किया जा रहा है। हालांकि वास्तविक उत्पादन में दो साल का समय लग जाएगा। इस दौरान जापान और वियतनाम से रेयर अर्थ मैग्नेट मंगाने पर काम चल रहा है। इनका यूज इलेक्ट्रिक गाड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है। केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी ने कहा है रेयर अर्थ मैग्नेट के घरेलू उत्पादन पर सब्सिडी योजना शुरू करने के बारे में 15 से 20 दिन में निर्णय लिया जाएगा। इस योजना के तहत सब्सिडी की मात्रा निर्धारित करने के लिए हितधारकों के साथ विचार-विमर्श जारी है।

भारी उद्योग मंत्रालय में सचिव कामरान रिजवी का कहना है कि यदि कुल प्रोत्साहन 1,000 करोड़ रुपये से अधिक होता है, तो योजना को मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा। कुमारस्वामी ने संवाददाताओं से कहा, हैदराबाद की एक कंपनी इसमें दिलचस्पी दिखा रही है। उसने वादा किया है कि वह इस साल के अंत यानी दिसंबर तक 500 टन की आपूर्ति करेगी। हमने खान मंत्री के साथ चर्चा की है। हमारे सचिव और हमारा मंत्रालय इस पर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 15 से 20 दिन के भीतर निर्णय लिया जाएगा। चीन द्वारा प्रमुख धातुओं के निर्यात पर हाल ही में लगाए गए प्रतिबंधों के कारण भारत सहित कई देशों में वाहन और सेमीकंडक्टर चिप के विनिर्माण में व्यापक व्यवधान उत्पन्न हुआ है। सचिव ने कहा कि दुर्लभ खनिज के वास्तविक उत्पादन में करीब दो वर्ष लगेंगे। इस दौरान सरकार उद्योग के साथ मिलकर जापान और वियतनाम सहित अन्य वैकल्पिक स्रोतों से खरीद की संभावना तलाशेगी। रिजवी ने कहा, 'आप जानते हैं कि जापान और वियतनाम में दुर्लभ खनिज उपलब्ध हैं। हम वहां से इसे लेने का प्रयास कर रहे हैं।' रेयर अर्थ मैग्नेट में नियोडिमियम-आयरन-बोरॉन शामिल है। इसका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहन में ट्रैक्शन मोटर और इलेक्ट्रिक वाहन एवं परंपरागत वाहनों में पावर स्टीयरिंग मोटर के लिए किया जाता है। सब्सिडी से रेयर अर्थ ऑक्साइड को चुंबक में बदलने के लिए प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित करने को निवेश मिल सकेगा। अधिकारियों ने बताया कि परमाणु ऊर्जा मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उपक्रम इंडियन रेयर अर्थ मैग्नेट्स लिमिटेड के पास ही रेयर अर्थ मैग्नेट का भंडार है। कंपनी के पास पास 1,500 टन चुंबक बनाने के लिए पर्याप्त रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। रिजवी ने कहा कि योजना केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास मंजूरी के लिए जाएगी या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रोत्साहन की मात्रा कितनी होगी। उन्होंने कहा, 'यह प्रोत्साहन के स्तर पर निर्भर करता है। यदि यह 1,000 करोड़ रुपये से कम है, तो (भारी उद्योग) मंत्री और वित्त मंत्री इसे कर सकते हैं। यदि यह 1,000 करोड़ रुपये से अधिक है, तो इसे मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा।' उन्होंने कहा कि हमें अभी तक आवश्यक सब्सिडी की मात्रा का पता नहीं है। स्टेकहोल्डर्स के साथ बातचीत जारी है और अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं। कोई 50 प्रतिशत चाहता है, कोई 20 प्रतिशत चाहता है, इसलिए यह प्रतिस्पर्धी बोली के अधीन होगा, तब ही हमें आवश्यक समर्थन की मात्रा का पता चलेगा।'

ऑपरेशन सिंदूर में अदाणी समूह की कंपनी के बनाए ड्रोन्स ने निभाई अहम भूमिका, गौतम अदाणी ने किया दावा

नई दिल्ली, एजेंसी। अदाणी समुह के प्रमुख गौतम अदाणी ने मंगलवार को दावा किया कि उनके समूह की ओर से बनाए गए ड्रोन और ड्रोन रोधी प्रणालियों ने ऑपरेशन सिंदूर में अग्रणी भूमिका निभाई थी। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से पहलगाम में हुए क्रूर आतंकवादी हमले जवाब में शुरू किया गया था। यह एक सटीक आतंकवाद रोधी हमला था। अपने समूह की वार्षिक शेयरधारक बैठक में बोलते हुए अदाणीनी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने आह्वान किया और हमने उसे पूरा किया। अदाणी डिफेंस की ओर से निर्मित हथियारों ने सटीक हमले किए, जबकि इसकी ड्रोन रोधी इकाइयों ने जवाबी खतरों से भारतीय संपत्तियों की रक्षा की।

उन्होंने कहा, हमारे ड्रोन आसमान में नजर रखने वाली आंखें और हमले की तलवार बन गए हैं और हमारी ड्रोन रोधी प्रणालियों ने हमारे बलों और नागरिकों की सुरक्षा में मदद की है। अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज (अदाणी डिफेंस की 26 प्रतिशत स्वामित्व वाली) और इस्राइल की एल्बिट सिस्टम्स की साझेदारी में विकसित स्काईस्ट्राइकर लोइटरिंग म्यूनिशन या कामिकेज़ ड्रोन 5-10 किलोग्राम तक के हथियार ले जा सकते हैं, 100 किलोमीटर तक की कम ऊंचाई पर चुपचाप उड़ सकते हैं, और लक्ष्य पर सटीक हमला कर सकते हैं।

हैकिंगः महत्वपूर्ण औजार

राकेश दुबे

जीवन के सभी क्षेत्रों में इंटरनेट और वेबसाइटों का उपयोग बढ़ता जा रहा है, इससे संबंधित अपराधों और हैकिंग के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। युद्ध में भी हैकिंग महत्वपूर्ण औजार बन रहा है जिसके अन्तर्गत दुश्मन की महत्वपूर्ण वेबसाइट को हैक कर जरूरी जानकारी प्राप्त की जाती है या उनके कार्यकलापों को ठप कर दिया जाता है। ऐसे खतरों से बचाने और देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए एथिकल हैकर्स द्वारा प्रयुक्त एथिकल हैकिंग की सहायता उल्लेखनीय होती है। विकसित और विकासशील देशों में एथिकल हैकर्स की मांग बढ़ती जा रही है और यह उभरता हुआ कैरियर बन रहा है । एथिकल हैकिंग के कार्य में समस्या-समाधान, नवाचार और प्रभावशाली कार्य का संयोजन होता है।

इसमें कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और डेटा को अनधिकृत पहुंच, उपयोग, प्रकटीकरण, व्यवधान, परिवर्तन या विनाश से सुरक्षित रखना शामिल है। साइबर हमलों का व्यक्तियों और संगठनों दोनों पर विनाशकारी प्रभाव हो सकता है। पिछले साल 80 प्रतिशत से अधिक भारतीय संगठनों ने कम से कम एक साइबर सुरक्षा घटना का अनुभव किया, जिससे लाखों डॉलर का नुकसान हुआ है। वेब हमले, फ़िशिंग और सप्लाई चेन हमले सबसे ज़्यादा दर्ज की गई घटनाओं में से थे। दुनिया में साइबर हमले बढ़ रहे हैं, तथा संगठनों को बढ़ती संख्या में परिष्कृत खतरों का सामना करना पड़ रहा है। भारत आईटी उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है जहां साइबर सुरक्षा के बढ़ते खतरे के परिदृश्य को देखते हुए, एथिकल हैकरों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है।

हैकर्स के अलग-अलग प्रकार हैं, जिनमें व्हाइट-हैट हैकर्स ~व्हाइट-हैट हैकर्स या एथिकल हैकर्स, सिस्टम की कमज़ोरियों की पहचान करने के लिए संगठनों के लिए काम करते हैं। वे अपने कौशल का उपयोग नैतिक उद्देश्यों के लिए करते हैं, नेटवर्क और सॉफ़्टवेयर सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। दूसरे होते हैं ब्लैक-हैट हैकर्स, ब्लैक-हैट हैकर्स कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाने, डेटा चुराने, सेवाओं को बाधित करने और नुकसान पहंचाने के लिए अनधिकृत व अवैध हैकिंग करते हैं। तीसरे होते हैं ग्रे हैट हैकर्स जो नैतिक और दुर्भावनापूर्ण हैकिंग के बीच की रेखा को पार करते हैं। वे बिना अनुमति सिस्टम हैक करते हैं, कमज़ोरियां उजागर कर ऑर्गेनाइजेशन की सहायता करने का इरादा रखते हैं। एथिकल हैकर्स सुरक्षा पेशेवर होते हैं जो सिस्टम में कमज़ोरियों की पहचान करने और उनका फ़ायदा उठाने के लिए दुर्भावनापूर्ण एक्टर्स यानी हैकर्स जैसी ही तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, अपने दुर्भावनापूर्ण समकक्षों के विपरीत, एथिकल हैकर्स उस संगठन की स्पष्ट अनुमति के साथ ऐसा करते हैं जिसका वे परीक्षण कर रहे हैं। वे डेटा चोरी करने या नुकसान पहुंचाने में रुचि नहीं रखते हैं। एथिकल हैकर्स आमतौर पर सुरक्षा कंपनियों, सरकारी एजेंसियों या बड़े संगठनों के लिए काम करते हैं। वे फ्रीलांसर या सलाहकार के रूप में भी काम कर सकते हैं।

भारत 2027 तक पांच ट्रिलियन डॉलर क्लब में होगा शामिल, पीयूष गोयल बोले- पीछे मुड़ने का सवाल नहीं

कोलकाता , एजेंसी। भारत अपनी आर्थिक प्रगति की रफ्तार पर सवार होकर दुनिया के बड़े देशों की कतार में मजबूती से कदम बढ़ा रहा है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भरोसा जताया है कि देश 2027 तक पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य हासिल कर लेगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक अस्थिरता और चुनौतियों के बावजूद भारत अपनी दिशा से डिगने वाला नहीं है।

कोलकाता में मर्चेंट्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एमसीसीआई) द्वारा आयोजित वर्चुअल सत्र में बोलते हुए गोयल ने कहा कि बीते एक दशक में भारत की आर्थिक नीतियों में केवल छोटे-मोटे बदलाव नहीं हुए, बल्कि इनमें 'क्रांतिकारी बदलाव' आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत न सिर्फ वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहा है, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर इतिहास भी रच रहा है।

तीन वर्षों में पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था

गोयल ने कहा कि आने वाले तीन वर्षों में भारत पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर पूरी मजबूती से अग्रसर है। यह लक्ष्य विकसित भारत 2047 के सफर की पहली बड़ी उपलब्धि होगी। उन्होंने यह भी जोड़ा कि बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मुश्किल हालात में ही खड़ी होती हैं, शांत पानी में कोई नाव पार नहीं लगती। यही भारत का समय है, जब हमें एकजुट होकर देश को उसकी सही जगह दिलानी है।

विदेशी मुद्रा भंडार पर बोले गोयल

मंत्री ने भारत की विकास नीति को समावेशी, टिकाऊ और ईमानदार करार देते हुए कहा कि सरकार सेवा, सुशासन और नवाचार को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने बताया कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार 698 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। साथ ही, बैंकिंग सेक्टर मजबूत हुआ है और महंगाई पर ऐतिहासिक नियंत्रण देखा गया है। उन्होंने इसे पिछले 11 वर्षों की दूरदर्शी नीतियों का परिणाम बताया।

भारत का बेहतरीन वक्त चल रहा- गोयल

अपने संबोधन में पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि भारत ने कभी फ्रैजाइल फाइव (कमजोर अर्थव्यवस्थाओं) में गिना जाता था, लेकिन अब वह दुनिया की शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स (एफटीए) का जिक्र करते हुए कहा कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ जैसे विकसित देशों के साथ जो व्यापार समझौते कर रहा है, वह भारतीय उद्योग, स्टार्टअप्स और एमएसएमई के लिए बेहतरीन अवसर लेकर आएंगे।

कैसे आगे बढ़ेगा भारत गोयल ने समझाया

तकनीक के क्षेत्र में भारत की ताकत पर जोर देते हुए गोयल ने कहा कि देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और 3डी प्रिंटिंग जैसे उभरते क्षेत्रों में भी अग्रणी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने युवाओं से डरने के बजाय नए अवसरों को अपनाने की अपील की। गोयल ने कहा कि यह विकास का चक्र है, जिसमें पैमाना बढ़ने से प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और यही निर्यात और समृद्धि को गति देता है। भारत की विकास गाथा हम सबकी साझी जिम्मेदारी है।

जियो में निवेश करना जीवन का सबसे बड़ा जोखिम था, मुकेश अंबानी ने किया बड़ा खुलासा

मुंबई, एजेंसी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने मैकिन्से एंड कंपनी को दिए एक विशेष साक्षात्कार में खुलकर बताया कि किस तरह जियो में निवेश करना उनके जीवन का सबसे बड़ा जोखिम था। उन्होंने कहा कि विश्लेषकों ने इस पर संदेह जताया था कि क्या भारत आवश्यक डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए तैयार है। फिर भी यह निर्णय रिलायंस इंडस्ट्रीज के परोपकारी सोच को ध्यान में रखते हुए लिया गया। इसका उद्देश्य भारत के डिजिटल परिवर्तन में योगदान देना है। अंबानी ने बताया कि मैंने बोर्ड से कहा कि सबसे बुरे हालात में भी अगर हमें वित्तीय लाभ नहीं हुआ, तो भी ठीक है, क्योंकि ये पैसा हमारा खुद का है। लेकिन इस प्रक्रिया में हमने अगर भारत को डिजिटाइज कर दिया, तो ये हमारा सबसे बड़ा परोपकारी कार्य होगा। अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के भविष्य पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि रिलायंस के लिए अब बदलाव यह है कि हम एक डीप-टेक और उन्नत विनिर्माण कंपनी बनने जा रहे हैं। हमने टेलीकॉम से शुरुआत की। 2021 में हमने 5त्न लॉन्च किया। इसका पूरा सिस्टम कोर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सब खुद बनाया। हमने 20 प्रतिशथ की मदद के लिए एरिक्सन और नोकिया का इस्तेमाल किया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमने जो 80 प्रतिशथ लगाया वह अच्छा है और हमारी टीम खुद पर बहुत ज्यादा गर्व न करें रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन ने आगे कहा कि कंपनी का बड़ा उद्देश्य समाज की जटिल समस्याओं को हल करना और देश व जनता के लिए संपत्ति निर्माण करना है। उन्होंने कहा कि एआई में अपना लक्ष्य तय किया है, समाज की जटिल समस्याओं का समाधान करना। इसके लिए हम उच्च जोखिम वाले त्नक्क गेम में नहीं जा रहे, बल्कि डाउनस्ट्रीम काम में ही विशेषज्ञता बनाएंगे। मुकेश अंबानी ने अपने पिता और रिलायंस के संस्थापक धीरूभाई अंबानी के विजन के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि पिताजी कहते थे कि अगर आप अरबपति बनने के लिए व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो आप मूर्ख हैं, आप कभी वहां नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आप एक अरब लोगों के जीवन पर प्रभाव डालने के लिए व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। उस स्थिति में, आपके पास सफलता की अच्छी संभावना है और साथ में धन भी आएगा।

दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में आने वाली है मंदी!

नई दिल्ली, एजेंसी। दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी वाले देश अमेरिका में अभी मंदी का खतरा टला नहीं है। देश के बड़े आर्थिक सूचकांक अब भी मंदी का संकेत दे रहे हैं। लीडिंग इकनॉमिक इंडेक्स (एलआईई) में मई में लगातार छठे महीने गिरावट आई है। पिछले 39 महीनों में 37 बार इसमें गिरावट आई है जो देश के इतिहास में सबसे लंबे दौर में से एक है। पिछले छह महीने में 5 फीसदी की सालाना दर से गिरावट आई है जो इस बात का संकेत है कि देश में अब भी मंदी का खतरा बना हुआ है। स्ढ्ढश्व अपने उच्चतम स्तर से 16 फीसदी गिर चुका है और यह नौ साल के अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका है। इतिहास पर नजर डालें तो 1960 के बाद हर बार मंदी से पहले एलईआई में लंबे समय तक गिरावट आई है। इससे इस बात की आशंका बढ़ गई है कि अमेरिका का इकॉनमी मंदी में जा सकती है। अमेरिका की इकॉनमी मंदी में फंसी तो इसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिलेगा। तकनीकी रूप से लगातार दो तिमाहियों में जीडीपी में गिरावट को मंदी कहा जाता है। इस बीच अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेड रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल का कहना है कि ब्याज दरों में कटौती की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि पॉलिसी बदलावों का दौर अभी चल रहा है और इकॉनमी पर उनके प्रभाव के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। अभी तो हम इंतजार कर रहे हैं। ट्रंप की टैरिफ नीति का इकॉनमी पर कुछ असर होगा लेकिन कितना प्रभाव होगा, यह देखना बाकी है।

डिपॉजिट पर अधिक निर्भरता से सार्वजनिक बैंकों की लागत बढ़ी, पर सुधार के संकेत मजबूत

नई दिल्ली, एजेंसी। देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) अपनी फंडिंग जरूरतों के लिए निजी बैंकों की तुलना में जमा (डिपॉजिट्स) पर अधिक निर्भर रहते हैं। वहीं, निजी क्षेत्र के बैंक अपनी वित्तपोषण जरूरतों के लिए उधारी (बॉरोइंग) का अधिक सक्रिय उपयोग करते हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार वित्तपोषण स्रोतों में इस अंतर के चलते पीएसबी को वित्तपोषण लागत में 20 से 30 आधार अंक का नुकसान हुआ है। बैलेंस शीट के लायबिलिटी पक्ष में, पीएसबी जमाराशियों पर लगभग 10 प्रतिशत अंक अधिक निर्भर है। इसमें बताया गया कि वित्त वर्ष 19 से पहले यह अंतर 50 से 70 बीपीएस था, जो पुनर्पूंजीकरण प्रयासों के बाद लागत अंतर में महत्वपूर्ण कमी का संकेत देता है। पीएसबी को संरचानत्क रूप से कमजोर माना जाता था, वे अब एक स्थायी सुधार की दिशा में बढ़ रहे हैं। बेहतर गवर्नेंस, बैलेंस शीट की सफाई, पुनर्पूंजीकरण और डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार जैसे कदमों से यह बदलाव आया है। इसके अलावा आय की गुणवत्ता और स्थिरता में भी सुधार देखा गया है। वित्त वर्ष 2025 में पीएसबी लोन बाजार हिस्सेदारी में 52 आधार अंक की वृद्धि हुई।

IPO की राह आसान बनाने के लिए एनएसई ने सेबी को दिया 13.88 अरब रुपये के भुगतान का ऑफर

नई दिल्ली, एजेंसी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने बाजार नियामक सेबी के साथ अपने कानूनी विवाद को निपटाने के लिए नियामक को 13.88 अरब रुपये यानी 1388 करोड़ रुपये (160 मिलियन डॉलर) का भुगतान करने की पेशकश की है। एनएसई ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि वह लंबे समय से टल रहे अपने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) को लाने की दिशा में आगे बढ़ सके। रॉयटर्स के अनुसार मामले से जुड़े तीन सूत्रों ने एनएसई के इस कदम की पुष्टि की है। एनएसई की ओर से पेश राशि भारत के इतिहास में बाजार नियामक के साथ किया गया सबसे बड़ा समझौता है।

भारत का सबसे बड़ा एक्सचेंज और दुनिया का सबसे सक्रिय डेरिवेटिव एक्सचेंज एनएसई 2019 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ मुकदमेबाजी में उलझा हुआ है। नियामक ने एक्सचेंज पर अपने सभी व्यापारिक सदस्यों को समान पहुंच प्रदान करने में विफल रहने के आरोपों के बाद 11 अरब रुपये का जुर्माना लगाया गया था। मामले से जुड़े दो सूत्रों के अनुसार, एनएसई और सेबी अदालत के बाहर समझौते के लिए बातचीत कर रहे हैं। एक सूत्र ने बताया कि नियामक तीन महीने के भीतर एक्सचेंज को यह प्रमाणपत्र दे सकता है कि उसे आईपीओ पर कोई आपत्ति नहीं है। एक अन्य सूत्र ने कहा, ÷यदि सब कुछ अपेक्षित समयसीमा के अनुसार हुआ तो एनएसई का आईपीओ अगले वर्ष मई से पहले बाजार में आ सकता है। रॉयटर्स के अनुसार, हालांकि इस मामले में एनएसई ने फिलहाल टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। सेबी की ओर से भी अब तक इस मामले में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं हा गया है। नकदी से समृद्ध मुंबई मुख्यालय वाला एनएसई 2016 से ही अपने कुछ सबसे बड़े निवेशकों को बाहर

निकालने के लिए सूचीबद्ध होने की कोशिश में जुटा है। लेकिन नियामक की जांच और फिर जुर्माने के कारण इस प्रक्रिया को रोक दिया गया था। एनएसई ने जुर्माने को अदालत में चुनौती दी, जिसने सेबी के आदेश के कुछ हिस्सों को अलग रखने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ नियामक ने बाद में देश की शीर्ष अदालत में अपील की थी। एनएसई के सबसे बड़े निवेशकों में भारतीय जीवन बीमा निगम शामिल है। इसकी एनएसई में 10.72त्न हिस्सेदारी है। इसके बाद भारतीय स्टेट बैंक की 7.76त्न हिस्सेदारी है। मॉर्गन स्टेनली के पास 1.58त्न तथा कनाडा पेंशन निवेश योजना बोर्ड के पास 1.60त्न हिस्सेदारी है। एनएसई की मुख्य घरेलू प्रतिद्वन्द्वी बीएसई लिमिटेड 2017 में शेयर बाजार में सूचीबद्ध हुई। दो सूत्रों ने बताया कि सेबी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से पहले एक्सचेंज की प्रणालियों और प्रक्रियाओं का निरीक्षण कर रहा है। सेबी ने फरवरी में एनएसई को पत्र लिखकर एक्सचेंज की आंतरिक प्रक्रियाओं के बारे में चिंता जताई थी। दो सूत्रों ने बताया कि यदि नियामक की ओर से इस समझौते को स्वीकार कर लिया जाता है तो इसके लिए भारत के शीर्ष न्यायालय की मंजूरी की आवश्यकता होगी।

टीसी के लिए 15 हजार की मांग, मां ने स्कूल प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप

छिंदवाड़ा। महर्षि विद्या मंदिर स्कूल, छिंदवाड़ा पर एक अभिभावक ने टीसी (स्थानांतरण प्रमाणपत्र) देने से इनकार करने और 15,000 रुपये की अवैध फीस मांगने का गंभीर आरोप लगाया है।शोभा उइके नामक महिला ने बताया कि उनका पुत्र अजित उइके, जो महर्षि विद्या मंदिर में कक्षा 10वीं में अध्ययनरत था, अब 11वीं कक्षा के लिए किसी अन्य स्कूल में प्रवेश लेना चाहता है। इसके लिए उन्होंने स्कूल प्रशासन से टीसी मांगी, लेकिन प्रिंसिपल श्रद्धा त्रिपाठी द्वारा 15,000 रुपये की अतिरिक्त फीस जमा करने की शर्त रखी गई।शोभा उइके का कहना है कि पूर्व में ऐसी किसी भी फीस की जानकारी नहीं दी गई थी और अब जब वे स्कूल बदलना चाहती हैं, तब यह दबाव बनाया जा रहा है।उन्होंने जिला प्रशासन से निवेदन किया है कि उनके बेटे की टीसी तत्काल उपलब्ध कराई जाए ताकि वह अन्य विद्यालय में प्रवेश ले सके और उसका शैक्षणिक भविष्य प्रभावित न हो।यह मामला शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के संज्ञान में लाया गया है। अगर आप भी इस तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं, तो तुरंत संबंधित विभाग को शिकायत करें।

गणेश बिहार कालोनी में किया पौधरोपण

छिंदवाड़ा । अग्रणी सामाजिक संस्था संकल्प वेलफेयर सोसाइटी एवं गणेश बिहार कालोनी के निवासियों द्वारा कालोनी के शिव मंदिर प्रांगण में बेलपत्र का पौधा लगाया साथ ही पौधा को संरक्षित करने उसकी देखरेख का जिम्मा भी कॉलोनीवासी ने लिया पौधारोपण के दौरान सभी ने जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत जल संरक्षण ,स्वच्छता की शपथ भी ली उक्त कार्यक्रम में समाजसेवी हरिशंकर सूर्यवंशी, अजय सराठे,दीपक पवार ,राजेंद्र पवार, सचिव संदीप अग्निहोत्री, प्रवक्ता डा.डी एस चौरे, राजा कराडे, तिजारे, पंडित प्रकाश शुक्ला, शिवांश विश्वकर्मा आदि सदस्य उपस्थित रहे कार्यक्रम के अंत में संस्था अध्यक्ष समाजसेवी चंद्रकांत विश्वकर्मा ने सभी
के प्रति आभार व्यक्त किया ।

पौने चार सौ किमी की पदयात्रा करेंगे सांसद

छिन्दवाड़ा। छिन्दवाड़ा और पांढुर्णा के निवासियों की सुख समृद्धि और शांति के लिए सांसद बंटी विवेक साहू छिन्दवाड़ा से पांढुर्णा होते हुए खंडवा तक पौने चार सौ किलोमीटर की पदयात्रा करेंगें। सांसद अपने चौथे संकल्प को पूरा करने के लिए 26 जून से 13 दिन की पदयात्रा शुरू करेंगे। इस 13 दिवसीय पदयात्रा के दौरान सांसद श्री साहू बारिश के मौसम में पचासों गांव एवं घने जंगलों से होते हुए अपने दृढ़ संकल्प के साथ इस पदयात्रा को पूरा करेंगें। सांसद ने इसके पूर्व उनके पहले संकल्प में छिन्दवाड़ा से जामसांवली तक 61 किमी, दूसरे संकल्प में भूराभगत से महादेव मंदिर तक 17 किमी की चढ़ाई एवं 17 किमी की वापसी कुल 34 किमी एवं तीसरे संकल्प में छिन्दवाड़ा से सिहोरामाल में स्थित रामेश्वर धाम 22 किमी तक पदयात्रा की थी। इन पदयात्राओं में भी सांसद श्री साहू ने जिलेवासियों के लिए सुख समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की थी। सांसद श्री साहू ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत छिन्दवाड़ा से जुन्नारदेव एवं सिंगोड़ी के गावों में करीब 125 किमी की पदयात्रा करते हुए ग्रामीणों से रूबरू होकर उनकी समस्याएं सुनते हुए उन्हें शासन की योजनाओं की जानकारी दी थी। सांसद छिन्दवाड़ा से खंडवा तक की पदयात्रा के पूर्व 26 जून को उनके निजनिवास के सामने स्थित हनुमान मंदिर से खंडवा दादाजी दरबार में भेंट करने के लिए ले जाये जा रहे निशान की विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगे। वे इस निशान को धारण कर अपनी पदयात्रा की शुरूआत करेंगे।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के पदों के लिये भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ

छिन्दवाड़ा। संचालनालय महिला एवं बाल विकास म.प्र. भोपाल के निर्देशानुसार छिंदवाड़ा जिले की छिंदवाडा शहरी परियोजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं /सहायिकाओं के रिक्त पदों की पूर्ति की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास परियोजना परियोजना छिन्दवाड़ा शहरी श्रीमती कृष्णा विश्वकर्मा ने बताया कि परियोजना छिन्दवाड़ा शहरी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 1 पद व आंगनवाड़ी सहायिका के 8 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों के लिये आवेदन एमपी ऑनलाईन चयन पोर्टल के माध्यम से किये जायेंगे। ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 4 जुलाई एवं अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन में संशोधन किये जाने की अंतिम तिथि 7 जुलाई निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि नियुक्ति के लिये केवल ऑनलाईन आवेदन ही स्वीकार किये जायेंगे। ऑफलाईन आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। जिन वार्ड में पद रिक्त है।

उपभोक्ता शिकायत शिविर में 153 शिकायतों पर किया त्वरित निराकरण

छिन्दवाड़ा। मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के छिंदवाड़ा/पांढुर्णा जिले में कंपनी के छिंदवाड़ा वृत्त कार्यालय, संचारण/संधारण के 8 संभागों जिनमें शहर संभाग छिंदवाड़ा, पूर्व संभाग छिंदवाड़ा, अमरवाड़ा, चौरई, सौंसर, पांढुर्णा, जुन्नारदेव व परासिया और इनके अंतर्गत आने वाले सभी वितरण केंद्रों में विद्युत उपभोक्ता समस्या निवारण शिविर संपन्न हुये । इन शिविरों में 153 शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से सभी 153 शिकायतों का मौके पर ही त्वरित निराकरण किया गया। मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता श्री खुशियाल शिववंशी ने बताया कि शिविर/जनसुनवाई में विद्युत प्रदाय संबंधी 79, बिल संबंधी 27, बंद/खराब मीटर संबंधी 21, नवीन कनेक्शन संबंधी 9 और अन्य प्रकार की 17 शिकायतें प्राप्त हुई। इस प्रकार कुल 153 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 153 शिकायतों का मौके पर ही तत्काल निराकरण किया गया। उन्होंने बताया कि विद्युत प्रदाय संधी 79, बिल संबंधी 7 बंद/खराब मीटर संबंधी 21, नवीन कनेक्शन संबंधी 09 और अन्य श्रेणी की 17 शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया ।

भाजपाआज मनाएगी संविधान हत्या दिवस, होंगे कार्यक्रम

लोकतंत्र सेनानियों का किया जाएगा सम्मान, भाजपा कार्यालय में प्रदर्शनी एवं आपातकाल पर संगोष्ठी का होगा आयोजन

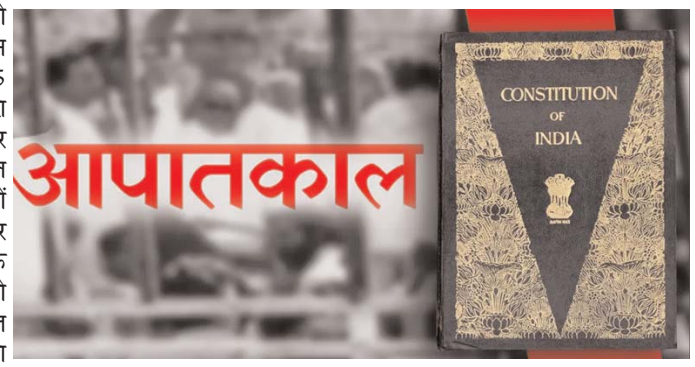

छिंदवाड़ा। 25 जून को भाजपा काला दिवस और संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाती है। 25 जून 1975 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी द्वारा संविधान की हत्या कर आपातकाल लगाया था। आपात काल के दौरान सभी विपक्षी पार्टी के सदस्यों और कार्यकर्ताओं को जेल में बंद कर दिया गया था। इस वर्ष आपात काल के 50 वर्ष पूरे हो रहे है। 25 जून को जिला भाजपा कार्यालय में आपात काल पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आपात काल एवं संविधान हत्या दिवस के कार्यक्रम हेतु भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव द्वारा वरिष्ठ भाजपा नेता विजय पांडे को जिला संयोजक एवं अजय सक्सेना को सह संयोजक नियुक्त किया गया है। जिला संयोजक विजय पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 जून को जिला भाजपा कार्यालय में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी आपातकाल दिवस और संविधान हत्या दिवस पर आपात काल की विभीषिका को प्रदर्शित करती हुई प्रदर्शनी लगाई जाएगी। आपातकाल की इस प्रदर्शनी का उद्घाटन बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल एवं भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव द्वारा दोपहर 12 बजे किया जाएगा। इसके उपरान्त लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान समारोह एवं आपातकाल पर संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इस संगोष्ठी में बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे। पांडे ने बताया कि संगोष्ठी में लोकतंत्र के सेनानी आपातकाल के अनुभव और तत्समय उनके ऊपर ढाए गए जुल्मों को उपस्थित जनों के साथ साझा करेंगे। उन्होंने बताया कि जिले में विभिन्न स्थानों पर आपातकाल की जानकारी हेतु क्यूआर कोड लगाए जाएंगे जिन्हें स्कैन करके आपातकाल की संपूर्ण विभीषिका को जाना सकेंगे। श्री पांडे ने बताया कि लोकतंत्र प्रहरी भारत घई, प्रमोद शर्मा, अरुण गदरे, शिखर पांडे, विजेंद्र चौहान, तरुण सोनी कार्यक्रम के आयोजन में विशेष सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

चौरसिया महिला समिति नागपंचमी पर करेगी प्रतिभाओं का सम्मान

छिंदवाड़ा । चौरसिया महिला समिति नाग पंचमी पर दो दिवसीय कार्यक्रम 28 एवं 29 जुलाई को करेंगी जिसमें हरियाली महोत्सव भजन एवं रामायण 29 तारीख को सामाजिक भोज एवं प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा, महिला समिति के अध्यक्ष रक्षा मुकेश चौरसिया ने बताया कि कार्यक्रम चौरसिया है मंगल भवन में होगा। बैठक में आशा रामकृष्ण, किरण अनिल, रेणुका मुन्ना लाल,संगीता घनश्याम,स्मिता हेमेंद्र,कल्पना नरेंद्र,कविता सुरेश,शालिनी विपिन सविता नीरज,रुचिका आशीष संध्या ओमप्रकाश, पश्मा गौरव, माधवी भुवन लाल, अनुसुइया, ज्योति, पुष्पा, सुधा, मधु, रूबी, निधि, संगीता, मनी, नीलू , ज्योति नरेंद्र एवं अन्य महिला उपस्थित थी।

नशे की हालत मे ऑटो चालक ने प्रसूति वार्ड में की मरीज महिला से अभद्रता ,पुलिस ने किया गिरफ्तार

शहडोल। इन दिनों जिला चिकत्सालय मे लगातार सुरक्षा व्यवस्था मे लापरवाही की बाते सामने आ रही है। सरकार के लाखो रुपये खर्च होने के बाद भी मरीज खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे है। जिला चिकित्सालय मे प्रसूति वार्ड मे नशे की हालत मे एक व्यक्ति द्वारा महिला मरीज से अभद्रता करने का मामला सामने आया है। पुलिस जानकारी के अनुसार बीती रात प्रसूती वार्ड में बिना रोक टोक के एक युवक रात करीब 12-01 बजे के आसपास अंदर घुस गया और मरीजों को परेशान करने लगा। यदि वार्ड मे रहे मरीजों की माने तो युवक एक मरीज महिला और एक बच्ची के पास पहुंच नशे की हालत मे गलत तरीके से हरकत करने लगा, इस दौरान मरीज के पास रही एक महिला ने इसका विरोध किया। मामला बढ़ता देख मौके से युवक भाग निकला। घटना की जानकारी लोगों ने पुलिस को दी। मौके मे पहुंची पुलिस ने अस्पताल में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवक की पहचान कर उसे कुछ ही देर मे हिरासत में लिया है। मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक दीवान ने बताया युवक की पहचान ऋषि गुप्ता पिता श्रीकांत गुप्ता निवासी कल्याणपुर के रूप में हुई है। युवक ऑटो चलाता है। बीती रात युवक वार्ड में घुसकर शोर मचा रहा था। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध बीएनएसएस की धारा 170 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए गिरफ्तार किया गया है।

तीन अलग-अलग स्थानों में लोग सर्पदंश का शिकार

शहडोल। जिले मे तीन अलग-अलग स्थानों में तीन लोग सर्पदंश का शिकार हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार मनोज सिंह निवासी ग्राम कनवाही रात करीब 9 बजे घर में सो रहा था, इस दौरान सर्पदंश का शिकार हो गया। इसी प्रकार रामबहोर पाव निवासी ग्राम लखवरिया शाम लगभग 7 बजे सरपदंश का शिकार हो गया। लोगो का जिला चिकत्सालय मे उपचार जारी है।

भूमि का सीमांकन ,नक्शे दुरुस्त करवाने तीन साल से परेशान आबिद जनसुनवाई में पहुंचा

पटवारी सोनी -बिल्डर जसूजा पर जमीन दबा लेने का आरोप

सांध्य प्रकाश बैतूल। जमीनों के बढ़ते दामो ने शहर से लगी जमीनों पर अवैध कब्जा किया जाना आम बात है। इधर राजस्व रिकार्ड या नक्शा हेराफेरी होने की शिकायत लगातार आ रही है। हालकि जिला कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने साफ निर्देश जारी किए है। कि जमीन का सही बटवारा नामान्तरण और सीमांकन समय अवधि के भीतर होना चाहिये। लेकिन पटवारी और आर आई को क्या और कितना फर्क पड़ता है। मायने यह रखता है। कंपनी गार्डन के आबिद अली ने निजी भूमि का सीमांकन के बाउजूद खसरा न. 77/1 का रकबा 0.881अनुसार पूरी जमीन नही दिलाये जाने से परेशान पीड़ित आबिद जनसुनवाई में शिकायत करने पहुँचा। पीड़ित आबिद अली ने पटवारी और बिल्डर पर उसकी 26 डिमि.जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। बताया कि ग्राम बटामा में जिसका खसरा नंबर 77/1 रकबा 0.881 हेक्टेयर है। सीमांकन करवाने के बाद आर आई और पटवारी ने उसे जमीन कम नापकर दी है।नक्शे में हेराफेरी किया जाना बताया है। अली ने शिकायत में लिखा कि तहसीलदार कोर्ट प्रकरण दर्ज कराया है। परंतु गठित टीम ने पिछले तीन साल में कार्यवाही पूरी नही गई। आर आई के प्रतिवेदन में सीमांकन के बाद मात्र 20 डिसमिल भूमि दी गई। 26 डिसमिल आज तक लंबित है। बताया कि उसकी खसरा 77/1 की भूमि खसरा 74/4 से लगी हुई है। जिसका फायदा उठाकर निश्चित हेराफेरी की गई। बिल्डर/ कालोनाइजर ने भूमि पर छोटे प्लॉटिंग कर दिया है। और भूमि पर काम जारी है। कहना है। कि धारा 115 के अंतर्गत नक्शे को दुरुस्त किया जा सकता था। अली ने पंकज निवासी मोती वार्ड हेमराज जसूजा गणेश वार्ड राजेश वागद्रे चंद्रशेखर वार्ड पर पटवारी श्री सोनी पर आपसी सांठ गांठ का आरोप लगाया है। सही सीमांकन एवं नक्शा सुधारकर दस्तावेज के आधार पर 0.881 हे. जमीन दिलाये जाने की जनसुनवाई में मांग की है।

कलेक्टर ने जनसुनवाई में नागरिकों की समस्याओं का किया निराकरण

औबेदुल्लागंज (संवाददाता)। कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित सभाकक्ष में प्रति मंगलवार की भांति आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा नागरिकों की समस्याओं पर सुनवाई करते हुए उनका निराकरण किया गया। कलेक्टर विश्वकर्मा ने कुछ प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों को शीघ्र आवश्यक कार्यवाही कर समस्याओं को निराकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले की विभिन्न तहसीलों से आए नागरिकों की समस्याओं की सुनवाई करते हुए वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को शीघ्र समाधान हेतु निर्देशित किया। साथ ही विकासखण्ड स्तर पर प्राप्त होने वाले आवेदनों को गंभीरतापूर्वक निराकृत करने के लिए कहा जिससे कि नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान हेतु जिला मुख्यालय पर ना आना पड़े। जनसुनवाई में प्राप्त अधिकांश आवेदन अतिक्रमण, खाद्यान्न पात्रता पर्ची, आर्थिक सहायता, विद्युत सहित शासकीय की विभिन्न योजनाओं के लाभ से संबंधित थे। जनसुनवाई में अपर कलेक्टर श्वेता पवार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से अनुभागों से एसडीएम, जनपद सीईओ, सीएमओ सहित विकासखण्ड स्तरीय अधिकारी जनसुनवाई में शामिल हुए।

भाजपा जिलाध्यक्ष ने रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अर्पित की श्रद्धांजलि

छिंदवाड़ा। भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने मंगलवार को रानी दुर्गावती चौक पहुंचकर रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की।भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को बांदा जिले के कालिंजर किले में हुआ था। दुर्गाष्टमी पर जन्म लेने के कारण उनका नाम 'दुर्गावती' रखा गया। वे कालिंजर के राजा कीर्तिसिंह चंदेल की इकलौती संतान थीं। उन्होंने कहा कि रानी दुर्गावती अकबर के सामने नहीं झुकी। रानी दुर्गावती के अदम्य साहस और वीरता के सामने अकबर के सेनापति आसफ खा को छल का सहारा लेना पड़ा। 24 जून 1564 को रानी दुर्गावती ने युद्ध लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव के साथ पूर्व निगम अध्यक्ष धर्मेन्द्र मिगलानी, वरिष्ठ भाजपा नेता विजय पांडे, अजय सक्सेना, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष संजय पटेल, सभापति राहुल बंटी उईके, पंडित प्रमोद शर्मा, माईकल पहाड़े, भारत घई, कृपाशंकर सूर्यवंशी, सुरेश उईके, सौरभ सूर्यवंशी, ओम चौरसिया, मनीष निर्मलकर, अरूण गद्रे, अनीष पटेल, तरूण सोनी, राकेश अग्रवाल, मोंटी शर्मा उपस्थित रहे।

नून्हारिया मेहरा समाज रानी दुर्गावती पुण्यतिथि मनाई

छिंदवाड़ा। नून्हारिया मेहरा समाज युवा प्रकोष्ठ द्वारा वीरांगना रानी दुर्गावती की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर समाज के सक्रिय सदस्य सुमित भांवरकर ने रानी दुर्गावती जी के अद्वितीय साहस, बलिदान और प्रशासनिक कार्यों पर प्रकाश डालते हुए युवाओं को उनके आदर्शों से प्रेरणा लेने का संदेश दिया। रानी दुर्गावती ने मुगलों के विरुद्ध वीरता से युद्ध करते हुए अपना बलिदान दिया था। उनका जीवन समर्पण, नारी शक्ति और आत्मसम्मान का प्रतीक है। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में समाज के अनेक पदाधिकारीगण उपस्थित रहे जिनमें कोमल भांवरकर, श्याम कोलारे, सोनू पाटिल, पिंटू बुनकर, आलेश बुनकर, मिथिलेश पटेलिया, अंकित सातनकर, राधे लाल भांवरकर, मंगल भांवरकर, एस.पी. भांवरकर, दीमक कोलारे, देवराव बुनकर सहित समाजजन उपस्थित थे। सभी ने रानी दुर्गावती के बलिदान को नमन करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।

नल-जल योजना के तहत 300 पाइप चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़

आष्टा। थाना आष्टा एवं सिद्दीकगंज थाना क्षेत्रों में नल-जल योजना के अंतर्गत पेयजल पाइपलाइन हेतु रखे गए कुल 300 पाइप (100 आष्टा व 200 सिद्दीकगंज से) चोरी कर लिए गए थे। पुलिस ने हरियाणा व राजस्थान के आरोपियों को गिरफ्तार कर पाइप, ट्रक व कार सहित कुल ?65 लाख का मशरूका बरामद किया है।

फरियादी मनीष विश्वकर्मा ने थाना आष्टा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि ग्राम भीमपुरा में नल-जल योजना के लिए रखे गए 100 पाइप चोरी हो गए हैं। विवेचना में यह भी सामने आया कि थाना सिद्दीकगंज क्षेत्र से 200 पाइप चोरी किए गए थे। प्रकरण में अपराध क्रमांक 292/25, धारा 303(2),34,112 व्हस्तथा तथा थाना सिद्दीकगंज में अपराध क्रमांक 108/25 धारा 303(2), 34, 112 बी एन एस का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला, अति. पुलिस अधीक्षक सुनीता रावत एवं एसडीओपी आकाश अमलकर के निर्देशन में थाना प्रभारी निरीक्षक गिरीश दुबे के नेतृत्व में अलग-अलग टीमों का गठन किया गया।

इंदौर-उज्जैन मेट्रो को मिलेगी रफ्तार, 20 हेक्टेयर में बनेगा आधुनिक डिपो, सरकारी जमीन की तलाश में मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन

इंदौर-उज्जैन मेट्रो परियोजना के लिए मेट्रो डिपो निर्माण हेतु लगभग 20 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है, जिसके लिए रेवती क्षेत्र को उपयुक्त माना गया है। पर्याप्त सरकारी भूमि न मिलने के कारण निजी भूमि पर भी विचार हो रहा है।

इंदौर और उज्जैन के बीच परिवहन को और अधिक सुगम व तीव्र बनाने के लिए इंदौर-उज्जैन मेट्रो परियोजना पर तेज़ी से काम किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा लगभग 20 हेक्टेयर (करीब 49.7 एकड़) भूमि पर मेट्रो डिपो निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

इंदौर व उज्जैन के आसपास पर्याप्त सरकारी भूमि न होने की वजह से डिपो के लिए सांवेर के नजदीक रेवती क्षेत्र को उपयुक्त विकल्प माना जा रहा है। हालांकि कॉर्पोरेशन निजी जमीन के विकल्पों पर भी विचार कर रहा है, लेकिन प्राथमिकता सरकारी भूमि के उपयोग को दी जा रही है।

कॉर्पोरेशन के लिए निजी भूमि की तुलना में सरकारी जमीन प्राप्त करना अपेक्षाकृत सरल प्रक्रिया है। सरकार आवश्यकता अनुसार किसी अन्य विभाग की भूमि कॉर्पोरेशन को आवंटित कर सकती है और उस विभाग को वैकल्पिक स्थान पर जमीन दी जा सकती है। दूसरी ओर, निजी भूमि अधिग्रहण में कई जटिलताएं होती हैं। इतनी बड़ी भूमि एक ही स्थान पर उपलब्ध नहीं होती, और इसे कई किसानों से मिलाकर जुटाना पड़ता है, जिसमें सहमति लेने में समय लगता है। इसके बाद मुआवज़े की प्रक्रिया भी अपनानी होती है, जिससे परियोजना की गति प्रभावित हो सकती है। कॉर्पोरेशन के अधिकारियों का कहना है कि डिपो निर्माण के लिए भूमि की तलाश जारी है, और इसके लिए रेवती क्षेत्र को प्रस्तावित किया गया है।

इंदौर और उज्जैन के बीच मेट्रो का संचालन हाइब्रिड मोड में किया जाएगा, जिसकी गति 135 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। फिलहाल इस प्रकार की प्रणाली का उपयोग दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में किया जा रहा है। पूर्व में सिंहस्थ से पहले इंदौर-उज्जैन मेट्रो शुरू करने की योजना थी, लेकिन लगभग 10 हजार करोड़ रुपये की अनुमानित लागत राज्य सरकार के लिए जुटा पाना चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। इसी कारण यह परियोजना सिंहस्थ से पहले पूरी होना संभव नहीं लग रहा है।

इंदौर-उज्जैन मेट्रो परियोजना के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने की जिम्मेदारी दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों को सौंपी गई है। यह रिपोर्ट जुलाई से अगस्त के बीच अंतिम रूप ले लेगी। इसमें परियोजना की कुल लागत, वित्तीय व्यवस्था, रूट अलाइनमेंट, डिपो निर्माण, स्टेशनों की योजना, भूमिगत मार्ग समेत अन्य तकनीकी और ढांचागत पहलुओं का विस्तृत विश्लेषण किया जा रहा है। पूरे प्रोजेक्ट पर लगभग 10 हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इंदौर से उज्जैन के बीच प्रस्तावित मेट्रो रेल परियोजना के तहत स्टेशन की संख्या और रूट अलाइनमेंट तय कर लिया गया है। कुल 47 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में आठ स्टेशन बनाए जाएंगे। पहला स्टेशन लवकुश चौराहा और अंतिम स्टेशन महाकाल लोक के सामने प्रस्तावित है। पूरे रूट का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा सड़क की मध्य रेखा (सेंट्रल लाइन) के अनुरूप तैयार किया जाएगा।

सजिया घाट के ग्रामीण अपनी समस्या को लेकर कलेक्टर के दरबार में बैठे

स्कूल अस्पताल जाने नहीं कोई रास्ता, कीचड़ में चलकर जाना पड़ता है ग्रामीणों को

दमोह। जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मध्य प्रदेश शासन में पशुपालन मंत्री लखन पटेल की पथरिया विधानसभा की ग्राम पंचायत सिजनीपुर का आदिवासी टोला सजिया घाट गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित ग्रामीणों ने कलेक्टर को आवेदन देकर अपनी समस्या सुनाई ग्राम वासियों का कहना है कि हमारे यहां सड़क की स्थिति इतनी खराब है कि बच्चो को स्कूल जाना हो बाजार जाना हो या फिर ग्राम में कोई बीमार हो जाए या किसी के घर डिलीवरी होना हो तो उसे कन्धा पर बैठ कर या खाट पर लेटाकर एंबुलेंस में ले जाना पड़ता है क्योंकि गांव तक एंबुलेंस नही पहुंचती इसलिए हम लोगो को स्वयं 3 किलोमीटर के कीचड़ भरे रास्ते में चलकर एंबुलेंस तक पहुंचाते हैं इसके बाद अस्पताल ले जाया जाता है इसी प्रकार ग्राम में पानी की समस्या भी बनी हुई है क्योंकि जो पाइपलाइन डाली गई है उसमें सप्लाई नहीं होती पानी की जैसे लोगों को पाने के लिए यहां वहां जाना पड़ता है जब उनसे पूछा आज आप कलेक्ट आए हैं जनसुनवाई में कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है इस दौरान कलेक्टर साहब ने क्या कहा आप लोगों से जिस पर ग्रामीणों ने बताया कि कलेक्टर साहब ने कहा है कि हम कल ही अधिकारियों को भेज कर दिखाते हैं।

मंत्रालय में टोपी एवं काली पट्टी पहनकर काम कर रहे कर्मचारी, पदोन्नति के नए नियमों का विरोध

भोपाल। मोहन यादव सरकार द्वारा कर्मचारियों अधिकारियों की पदोन्नति के लिए जारी किए गए नए नियमों के विरोध में आज से मंत्रालय में विरोध शुरू हो गया है। मंत्रालय में पदस्थ अनारक्षित वर्ग के अधिकारी कर्मचारी आज दफ्तर में सरकार के पदोन्नति नियम के विरोध में काली टोपी और काली पट्टी लगाकर काम करने पहुंचे

हैं और कल मंत्रालय में सामान्य, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारी एकजुट होकर प्रदर्शन कर आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। उधर सपाक्स (स्पीक) ने भी इस मामले को लेकर आंदोलन की रणनीति बनाने 29 जून को बैठक बुलाई है जिसमें सभी कर्मचारी अधिकारी संगठनों को बुलाया गया है।

मंत्रालय अधिकारी कर्मचारी सेवा संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक ने मंत्रालयीन कर्मचारियों अधिकारियों से कहा है कि अभी नए पदोन्नति नियमों और पुरानी व्यवस्था में पदोन्नति के 36 प्रतिशत पद आरक्षित वर्ग को मिलेंगे। इसमें 20 प्रतिशत एसटी और 16 प्रतिशत एससी वर्ग के लोग होंगे। इसके बाद अनारक्षित वर्ग के लिए जो पदोन्नति के 64 प्रतिशत पद बचेंगे उसमें भी आरक्षित वर्ग के लोग वरिष्ठता के हिसाब से आएंगे और अनारक्षित वर्ग का हक मारेंगे। उन्होंने कहा कि आरक्षित वर्ग का कोई व्यक्ति ऊंचे पद पर पहुंचता है तो लम्बे समय तक रहता है और सामान्य, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकारी कुछ समय के लिए ही पद पर रहकर रिटायर हो जाता है। क्या हमारा प्रदेश की और राष्ट्र की उन्नति में कोई योगदान नहीं है। क्या सामान्य और पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग साइबेरिया से आए हैं। इस तरह की तुष्टिकरण की कार्यवाही सरकार क्यों कर रही है।

मंत्रालय में पदों के आरक्षण की स्थिति

अंडर सेक्रेट्री के 65 पद में से 58 पदों पर आरक्षित वर्ग के अधिकारी पदस्थ। उप सचिव के 14 पद हैं जिसमें से सभी पदों पर आरक्षित वर्ग के अफसर पदस्थ। अपर सचिव के तीन पद हैं और तीनों पर आरक्षित वर्ग के अफसर पदस्थ। स्पीक के अध्यक्ष बोले- 29 को करेंगे सभी संगठनों के साथ मीटिंग। दूसरी ओर सपाक्स (स्पीक) के अध्यक्ष डॉ केएस तोमर ने कहा कि मंगलवार को मंत्रालय में हुई मीटिंग में वह भी शामिल हुए थे। कर्मचारियों, अधिकारियों को लोकसेवा पदोन्नति नियम 2025 के उन प्रावधानों की जानकारी दी गई है जो अनारक्षित वर्ग का हक मारने वाले हैं। तोमर ने कहा कि सरकार तो अनारक्षित वर्ग की बात ही नहीं सुनना चाहती है, इसलिए आंदोलन और कोर्ट जाने के अलावा इस वर्ग के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। ऐसे में 29 जून को राजधानी के नार्मदीय भवन में इस वर्ग के हितों को लेकर रणनीति बनाने सभी कर्मचारी अधिकारी संगठनों की बैठक बुलाई गई है।

प्रदेश में पांच सक्रिय मौसम प्रणालियों से मूसलधार बारिश, 16 जिलों में रेड अलर्ट

भोपाल। मध्य प्रदेश में इन दिनों मानसून अपने पूरे जोर पर है। प्रदेश में पांच सक्रिय मौसम प्रणालियों – दो ट्रफ लाइन, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन और दो लो प्रेशर ज़ोन – के असर से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार, ये सिस्टम मिलकर प्रदेशभर में भारी बारिश की स्थिति बना रहे हैं, जिससे न केवल शहरों में जलभराव की स्थिति बन गई है, बल्कि तापमान में भी गिरावट आई है। सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉ. दिव्या ई. सुरेंद्रन के मुताबिक, यह स्थिति आगामी चार दिनों तक बनी रह सकती है। मौसम विभाग ने बुधवार को ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, रायसेन, देवास, धार, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला और बालाघाट जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में अगले 24 घंटे के भीतर साढ़े 4 इंच तक बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर समेत पूरे प्रदेश में यलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है।

18 जिलों में बरसा पानी, उज्जैन में 2.1 इंच बारिश

मंगलवार को प्रदेश के 18 से अधिक जिलों में बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे अधिक वर्षा उज्जैन में हुई, जहां 9 घंटे में 2.1 इंच पानी बरसा। सतना में 1 इंच, जबकि नर्मदापुरम, नौगांव (छतरपुर) और मलाजखंड (बालाघाट) में आधा इंच बारिश दर्ज हुई। साथ ही भोपाल, बैतूल, गुना, राजगढ़, जबलपुर, दमोह, सागर, उमरिया, शाजापुर, आगर-मालवा, सीहोर, रतलाम और शिवपुरी में भी रुक-रुक कर बारिश होती रही। बारिश के कारण अधिकांश स्थानों पर दिन का तापमान गिरा, और पचमढ़ी प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 23.2एष्ट दर्ज किया गया।

हर दिन तेज बारिश के संकेत

ग्वालियर, शिवपुरी, सीहोर, सागर, दमोह, रायसेन, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, रीवा और सीधी में भारी बारिश का अलर्ट है। यहां 24 घंटे में 4.5 इंच तक वर्षा हो सकती है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर में भी यलो अलर्ट जारी है।

तापमान में गिरावट, जलभराव से जनजीवन प्रभावित

लगातार बारिश से प्रदेश के कई जिलों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। कुछ निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं और यातायात बाधित हो रहा है। वहीं तापमान में गिरावट के कारण मौसम सुहावना हो गया है, लेकिन किसानों और आम नागरिकों के लिए यह मिश्रित प्रभाव ला सकता है। फसलों के लिए ज्यादा बारिश लाभकारी है, लेकिन जलभराव और भूस्खलन जैसी स्थितियों से सतर्क रहना जरूरी है।

नागरिकों से सतर्क रहने की अपील

राज्य प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी संबंधित जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे बिना आवश्यक कारण घर से बाहर न निकलें, और बिजली कड़कने या तेज हवा चलने की स्थिति में खुले स्थानों से बचें।

अगले चार दिन मौसम ऐसा रहेगा

26 जून: भोपाल, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, सागर, रायसेन, नर्मदापुरम, दमोह, जबलपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला और डिंडोरी में भारी वर्षा का अनुमान है। अन्य जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की आशंका है।

27 जून: सागर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, दमोह, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, रीवा, सीधी और सिंगरौली में भारी बारिश संभव है। बाकी क्षेत्रों में भी मानसून सक्रिय रहेगा।

28 जून: ग्वालियर, शिवपुरी, सीहोर, सागर, रायसेन, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, दमोह, छिंदवाड़ा, रीवा और सीधी जिलों में फिर से भारी बारिश का पूर्वानुमान है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर जैसे प्रमुख शहरों में भी मध्यम से तेज बारिश जारी रहेगी।

भोपाल में आज महापौर मालती राय ने आईएसबीटी स्थित कार्यालय पर जोन 05 की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया। आर के सिंह बघेल, वृजुला सचान, जोनल अधिकारी उपस्थित रहे।

भोपाल में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवकुमार कक्काजी द्वारा अमेरिका से मुक्त व्यापार समझौता एवं किसानो की बुनियादी समस्याओ के सन्दर्भ में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया।

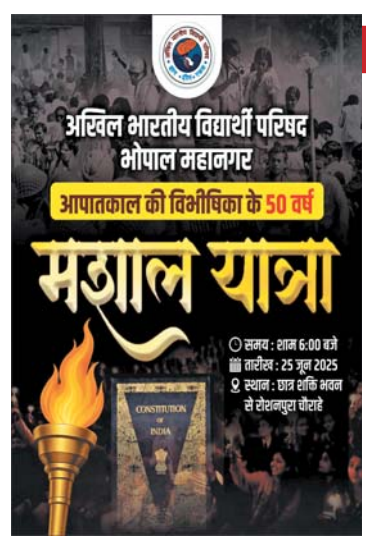

सोशल मीडिया से

आपातकाल का
काला दिवस
25-26 जून 1975

"संविधान हत्या दिवस"
राष्ट्रीय कार्यक्रम
25 जून 2025 से 25 जून 2026

लोकतंत्र सेनानी प्रादेशिक सम्मेलन
26 जून, 2025
मुख्यमंत्री निवास, श्यामला हिल्स, भोपाल

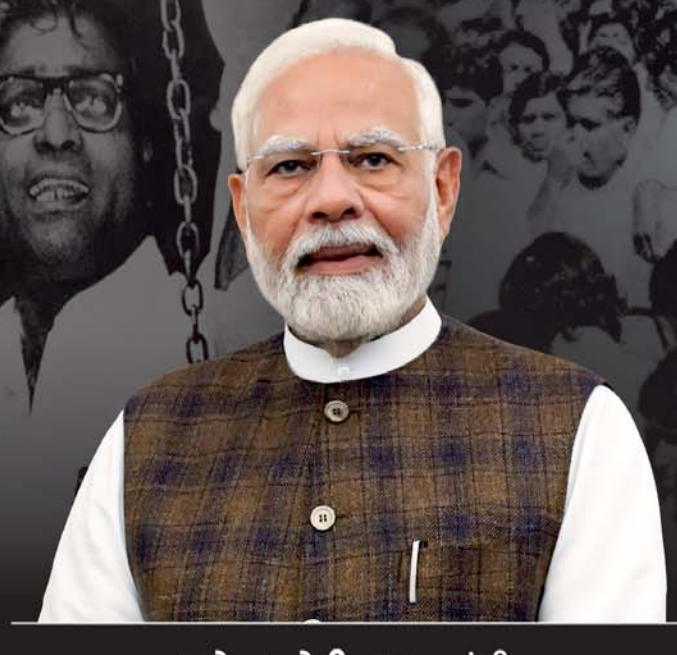

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उस अन्यायपूर्ण दौर को हम कभी नहीं भूलेंगे, आपातकाल के दरमियान लोकतंत्र सेनानियों ने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी और लोकतंत्र की रक्षा की। आज उनके कारण हमारा लोकतंत्र दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ है। उम्मीद करेंगे कि जीवन में ऐसा काला दिवस कभी ना आए।
मैं लोकतंत्र सेनानियों को बधाई देता हूं जिनके कारण आज लोकतंत्र जिंदा है। इतिहास उन्हें सदैव याद रखेगा। इसके साथ ही प्रदेश के नागरिकों को भी शुभकामनाएं देता हूं।

- डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

कार्यक्रम की गतिविधियां

- जनभागीदारी के माध्यम से देश के सभी राज्यों और जिलों में लोकतंत्र के सशक्तिकरण, लोकतंत्र की जननी भारत और लोकतंत्र अमर रहे के संदेश के साथ सेंगोल को नमन करते हुए वाहन रैलियों के माध्यम से निश्चित गंतव्य तक पहुंच कर सभी तक संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों का संदेश प्रसारित किया जाएगा
- समस्त विद्यालय और महाविद्यालयों में निबंध प्रतियोगिताएं, सेमिनार और भाषणों के माध्यम से विषयवस्तु की जानकारी युवाओं तक पहुंचाई जाएगी
- 25 जून 2025 को लोकतंत्र के प्रति समर्पण के भाव और जज्बे के प्रतीक रूपी 6 मशाल/ई-टॉर्च की मशाल यात्रा का शुभारंभ दिल्ली से होगा
- ये मशाल यात्रा देशभर में माय भारत वॉलंटियर्स के माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों का संदेश प्रसारित करेगी, प्रत्येक राज्य में इस मशाल का स्वागत होने के पश्चात 21 मार्च 2026 को इस मशाल यात्रा का समापन नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होगा

सीधा प्रसारण
@Cmmadhyapradesh
@jansampark.madhyapradesh
@Cmmadhyapradesh
@jansamparkMP
JansamparkMP

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी
D-11050/25
आकल्पन : म.प्र. माध्यम/2025